

#### असाधारण

#### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

### PUBLISHED BY AUTHORITY

**सं**. 1527] No. 1527] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 20, 2015/ आषाढ़ 29, 1937 NEW DELHI, MONDAY, JULY 20, 2015/ASADHA 29, 1937

> वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2015

का.आ. 1952(अ).—जबिक आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पिठत उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 11.08.1998 की अधिसूचना सं. का.आ. 676(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "एसओएस चिन्डून विलेजिस ऑफ इंडिया-चटनाथ होम्स,7, राजा कृष्णा रोड, टेनमपेट, चेन्नई-60018" द्वारा "तांब्रम पूर्व, चेन्नई, तिमलनाडु में एसओएस चिन्डून्स विलेजिज स्कूल के भवन के निर्माण और चलाने" की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अविध के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 8 पर अधिसूचित किया था; और जिसे बाद में दिनांक 20.06.2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 568(अ) के तहत निर्धारण वर्ष 2002-2003 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 05.07.2014 की अधिसूचना सं. का.आ. 793(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-05 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 15.02.2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 246(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 18.05.2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 1258(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 18.05.2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 1258(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए और बढ़ा दिया गया था; और का.आ. 2886(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए और बढ़ा दिया गया था।

और जबिक दिनांक 15 फरवरी, 2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 246(अ) द्वारा अनुमानित लागत को 60.00 लाख रू० से बढ़ाकर 105.00 लाख रू० कर दिया गया था; और जिसे दिनांक 18.05.2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 1258(अ) द्वारा अनुमानित लागत को 105.00 लाख रू० से बढ़ाकर 150 लाख रू० कर दिया गया था और

3152 GI/2015 (1)

दिनांक 27 दिसंबर, 2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 2886(अ.) द्वारा अनुमानित लागत को 150.00 लाख रूपये से बढ़ाकर 175.00 लाख रूपए कर दिया गया था;

और जबिक उक्त परियोजना या स्कीम के 18 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबिक परियोजना लागत को 175.00 लाख रूपए से 225.00 लाख रूपए तक बढ़ाए जाने की संभावना है।

और जबिक सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय सिमिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस सिमिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अविध के लिए बढ़ाने और परियोजना लागत को 175.00 लाख रूपए से 225.00 लाख रूपए तक संशोधित करने की सिफारिश की है:

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पिठत उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा एसओएस चिल्ड्रन विलेजिस ऑफ इंडिया-चटनाथ होम्स,7, राजा कृष्णा रोड, टेनमपेट, चेन्नई-60018" द्वारा चलाई जा रही "तांब्रम पूर्व, चेन्नई, तिमलनाडु में एसओएस चिन्ड्रन्स विलेजिज स्कूल के भवन के निर्माण और चलाने" की परियोजना अथवा स्कीम को विन्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अविध अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 और 2017-18 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है और;

(ख) दिनांक 11 अगस्त, 1998 की उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 676(अ.) को निम्नलिखित आशय के लिए और आगे संशोधित करती है नामत:-

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 8 के सामने तालिका में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35कग के तहत कटौती के रूप में अनुमित दी जाने वाली लागत की अधिकतम राशि से संबंधित कालम (4) में "175.00 लाख रूपये" अक्षरों, अंकों और शब्दों को "225.00 लाख रूपये" अक्षरों, अंकों और शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[सं. 165/2015 /फा. सं. वी-27015/2/2015-एस ओ (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

# MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2015

**S.O. 1952(E).**—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.676(E) dated the 11<sup>th</sup> August, 1998, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 8, "Construction of a school building and running of SOS Children's Village at Tambaram East, Chennai, Tamilnadu" by "SOS Children Villages of India-Chatnath Homes, 7, Raja Krishna Road, Teynampet, Chennai – 600018", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1999-2000, which was extended further vide notification number S.O.568(E) dated the 20<sup>th</sup> June, 2001 for a period of three years beginning with assessment year 2002-2003, which was extended further vide notification number S.O.793(E) dated the 5<sup>th</sup> July, 2004 for a period of three years beginning with financial year 2004-2005, which was extended further vide notification number S.O.246(E) dated the 15<sup>th</sup> February, 2007 for a period of three years beginning with financial year 2006-2007, which was extended further vide notification number S.O. 1258(E) dated 18<sup>th</sup> May, 2009 for a period of three years beginning with financial year 2002-10 and which was extended further vide notification number S.O. 2886(E) dated 27<sup>th</sup> December, 2012 for a period of three years beginning with financial year 2012-13;

And whereas by notification number S.O.246(E) dated the 15<sup>th</sup> February, 2007 the estimated cost was enhanced from Rs.60.00 lakh to Rs.105.00 lakh, vide notification number S.O.1258(E) dated 18<sup>th</sup> May, 2009 the estimated cost was enhanced from Rs. 105.00 lakh to 150 lakh and vide notification number S.O. 2886(E) dated 27<sup>th</sup> December, 2012 the estimated cost was enhanced from Rs. 150.00 lakh to Rs. 175.00 lakh;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond eighteen years;

And whereas the project cost is likely to enhance from Rs. 175.00 lakh to Rs. 225.00 lakh;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years and amending the project cost from Rs.175.00 lakh to Rs.225.00 lakh;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961),- (a) hereby notifies the scheme or project "Construction of a school building and running of SOS Children's Village at Tambaram East, Chennai, Tamilnadu", which is being carried out by "SOS Children Villages of India-Chatnath Homes, 7, Raja Krishna Road, Teynampet, Chennai – 600018", for a period of three years commencing with the financial year 2015-16 i.e. 2015-16, 2016-17 and 2017-18 and;

(b) further amends the said notification number S.O.676(E) dated the 11<sup>th</sup> August, 1998, to the following effect, namely:-

In the said notification, in the Table against serial number 8, in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35AC of Income Tax Act, 1961, for the letters, figures and word "Rs.175.00 lakh" the letters, figures and word "Rs.225.00 lakh" shall be substituted.

[No. 165/2015/ F. No. V.27015/2/2015-SO(NAT.COM)] MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2015

का.आ. 1953(अ).—जबिक आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 15.02.2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 234(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "शांति समाज सेवी समिति, 2/377, खटराना स्ट्रीट, फारूखाबाद-209625 (उत्तर प्रदेश)" द्वारा 'स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर प्रदान करने" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2006-07 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अविध के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 13 पर अधिसूचित किया था; जिसे बाद में दिनांक 14.10.2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 2610(अ.) के तहत वित्तीय वर्ष 2009-10 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 12 मार्च, 2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 664(अ) के तहत वित्तीय वर्ष 2012-13 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबिक उक्त परियोजना या स्कीम के 9 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबिक सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अविध के लिए बढाने की सिफारिश की है:

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, "शांति समाज सेवी सिमिति, 2/377, खटराना स्ट्रीट, फारूखाबाद-209625 (उत्तर प्रदेश)" द्वारा चलाई जा रही "स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर प्रदान करने" की परियोजना अथवा स्कीम को 71.40 लाख रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अविध अर्थात 2015-16, 2016-17 और 2017-2018 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 166/2015 /फा. सं. वी -27015/2/2015-एस ओ (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

New Delhi, the 20th July, 2015

**S.O. 1953(E).**— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 234(E) dated the 15th February, 2007, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 13, "To provide health and employment opportunities" by "Shanti Samaj Sevi Samiti, 2/377, Khatrana Street, Farrukhabad – 209625, (Uttar Pradesh)", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2006-2007, which was extended further vide notification number S.O. 2610(E) dated 14th October,2009 for a period of three years beginning with the financial year 2009-10 and which was extended further vide notification number S.O. 664(E) dated 12th March,2013 for a period of three years beginning with the financial year 2012-13;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond nine years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "To provide health and employment opportunities" which is being carried out by "Shanti Samaj Sevi Samiti, 2/377, Khatrana Street, Farrukhabad – 209625, (Uttar Pradesh)", without any change in the approved cost of Rs. 71.40 lakh, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial year 2015-16 i.e. 2015-16, 2016-17 and 2017-18.

[No. 166/2015/ F. No. V.27015/2/2015-SO(NAT.COM)] MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2015

का.आ. 1954(अ).—जबिक आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक २९.०३.१९९४ की अधिसूचना सं. का.आ. २६७(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "एसओएस चिल्डून विलेजिस ऑफ इंडिया, ए-7, निजामुद्दीन (पश्चिम), नई दिल्ली-110013" द्वारा "मुफ्त कपड़े, शिक्षा और आश्रय और निराश्रित, अनाथ और परितयक्त बच्चों को पारिवारिक वातावरण प्रदान करने के लिए 27 मौजूदा गांवों के प्रशासन और अनुसरण" की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1995-1996 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 6 पर विनिर्दिष्ट किया था और जिसे बाद में दिनांक 19.05.1997 की अधिसूचना सं. का.आ. 390(अ) के तहत निर्धारण वर्ष 1998-1999 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 21.09.2000 की अधिसूचना सं. का.आ. 852(अ) द्वारा निर्धारण वर्ष 2001-02 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 09.05.2003 की अधिसूचना सं. का.आ. 527(अ) द्वारा निर्धारण वर्ष 2004-05 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 05.07.2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1006(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 25.03.2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 833(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 14.05.2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 1074(अ.) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबिक दिनांक 14.11.2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1604(अ) द्वारा अनुमानित लागत को 3291.00 लाख रू० से बढ़ाकर 4791.00 लाख रू० कर दिया गया था; और जिसे दिनांक 16.07.2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 1165(अ) द्वारा अनुमानित लागत को 4791.00 लाख रू० से बढ़ाकर 50.00 करोड़ रू० कर दिया गया था और दिनांक 25.07.2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 1849(अ) द्वारा अनुमानित लागत को 50.00 करोड़ रूपए से बढ़ाकर

100.00 करोड़ रूपए कर दिया गया था और दिनांक 14 मई, 2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 1074(अ.) द्वारा अनुमानित लागत को 100.00 करोड़ रूपये से 150.00 करोड़ रूपए तक बढ़ा दिया गया था;

और जबिक उक्त परियोजना या स्कीम के 21 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबिक परियोजना लागत को 150.00 करोड़ रूपए से 200.00 करोड़ रूपए तक बढ़ाने की संभावना है;

और जबिक सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अविध के लिए बढ़ाने और परियोजना लागत को 150.00 करोड़ रूपए से 200.00 करोड़ रूपए तक संशोधित करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा एसओएस चिल्ड्रन विलेजिस ऑफ इंडिया, ए-७, निजामुद्दीन (पश्चिम), नई दिल्ली-110013" द्वारा चलाई जा रही "मुफ्त कपड़े, शिक्षा और आश्रय और निराश्रित, अनाथ और परितयक्त बच्चों को पारिवारिक वातावरण प्रदान करने के लिए 27 मौजूदा गांवों के प्रशासन और अनुसरण" की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अविध अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 और 2017-18 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है और;

(ख) दिनांक 29 मार्च, 1994 की उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 267(अ) को निम्नलिखित आशय के लिए और आगे संशोधित करती है नामत:-

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 8 के सामने तालिका (4) में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35कग के तहत कटौती के रूप में अनुमित दी जाने वाली लागत की अधिकतम राशि से संबंधित है, में "150.00 करोड़ रूपये" अक्षरों, अंकों और शब्दों को "200 करोड़ रूपये" अक्षरों, अंकों और शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[सं. 167/2015 /फा. सं. वी-27015/2/2015-एस ओ (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2015

S.O. 1954(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.267(E) dated the 29<sup>th</sup> March, 1994, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 6, "Administration and maintenance of 27 existing villages for providing free clothing, education and shelter and family environment to destitute, orphaned and abandoned children" by SOS Children's Villages of India, A-7, Nizamuddin (West), New Delhi-110013, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1995-1996, which was extended further vide notification number S.O.390(E) dated the 19<sup>th</sup> May, 1997 for a period of three years beginning with assessment year 1998-1999, which was extended further vide notification number S.O.852(E) dated the 21<sup>st</sup> September, 2000 for a period of three years beginning with assessment year 2001-2002, which was extended further vide notification number S.O.527(E) dated the 9<sup>th</sup> May, 2003 for a period of three years beginning with assessment year 2004-2005, which was extended further vide notification number S.O.1006(E) dated the 5<sup>th</sup> July, 2006 for a period of three years beginning with financial year 2006-2007 and which was extended further vide notification number S.O.833(E) dated the 25<sup>th</sup> March, 2009 for a period of three years beginning with financial year 2009-10 and which was extended further vide notification number S.O.1074(E) dated the 14<sup>th</sup> May, 2012 for a period of three years beginning with financial year 2012-13;

And whereas by notification number S.O.1604(E) dated the  $14^{th}$  November, 2005 the estimated cost was enhanced from Rs. 3291.00 lakh to Rs.4791.00 lakh, vide notification number S.O.1165(E) dated the  $16^{th}$  July, 2007 the estimated cost was further enhanced from Rs. 4791.00 lakh to Rs.50.00 crore and vide notification number S.O.1849(E) dated the  $25^{th}$  July, 2008 the estimated cost was further enhanced from Rs.50.00 crore to Rs.100.00 crore

and vide notification number S.O. 1074(E) dated the 14<sup>th</sup> May, 2012 the estimated cost was further enhanced from Rs.100.00 crore to Rs. 150 crore;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond twenty one years;

And whereas the project cost is likely to enhance from Rs. 150 crore to Rs. 200.00 crore;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years and enhancing the project cost from Rs. 150 crore to Rs. 200 crore;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (a) hereby notifies the scheme or project "Administration and maintenance of 27 existing villages for providing free clothing, education and shelter and family environment to destitute, orphaned and abandoned children" being carried out by "SOS Children's Villages of India, A-7, Nizamuddin (West), New Delhi-110013", as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with the financial year 2015-16 i.e. 2015-16, 2016-17 and 2017-18;

(b) further amends the said notification number S.O. 267(E) dated the 29<sup>th</sup> March, 1994, to the following effect, namely:—

In the said notification, in the Table against serial number 8, in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section of 35AC of Income Tax Act, 1961 for the letters, figures and word "Rs. 150 crore" the letters, figures and word "Rs. 200 crore" shall be substituted.

[No. 167/2015/ F. No. V.27015/2/2015-SO(NAT.COM)] MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2015

का.आ. 1955(अ).—जबिक आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 20.08.1997 की अधिसूचना सं. का.आ. 591(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "अंजिल (ग्रामीण स्वास्थ्य और विकास के लिए सोसायटी), डाक-राणासेन, वाया हरसोल, तालुका-प्राणितज, साबरकांठा, गुजरात-383305" द्वारा "राणासेन-हरसोल-साबरकांठा में शिक्षण और बाल गतिविधि हाल/अहाता दीवार का निर्माण, उपस्कर, वाहन, साज-सामान और अंजिल अस्पताल, टी.बी. केंद्र और बच्चों और शैक्षणिक गतिविधयों को चलाने" की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1998-99 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अविध के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 2 पर अधिसूचित किया था; और जिसे बाद में दिनांक 21.09.2000 की अधिसूचना सं. का.आ. 872(अ) के तहत निर्धारण वर्ष 2001-2002 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 31.03.2003 की अधिसूचना सं. का.आ. 350(अ) द्वारा निर्धारण वर्ष 2004-05 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 21.01.2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 241(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 14.05.2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 1092(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 14.05.2012 की अधिसूचना सं. का.आ.

और, जबिक दिनांक 05.7.2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1003(अ) द्वारा अनुमानित लागत को 25.00 लाख रूपये की कॉपर्स निधि सिहत 33.00 लाख रू0 से बढ़ाकर 25.00 लाख रूपये की कॉपर्स निधि सिहत 171.00 लाख रू0 कर दिया गया था; और जिसे दिनांक 18.05.2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 1140(अ) द्वारा आगे संशोधित करके 25.00 लाख रूपये की कॉपर्स निधि सिहत 171.00 लाख रू0 से बढ़ाकर 25.00 लाख रूपये की कॉपर्स निधि सिहत 571.00 लाख रू0 कर दिया गया था;

और जबिक उक्त परियोजना या स्कीम के 18 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबिक सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय सिमिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस सिमिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अविध के लिए बढाने की सिफारिश की है:

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा अंजिल (ग्रामीण स्वास्थ्य और विकास के लिए सोसायटी), डाक-राणासेन, वाया हरसोल, तालुका-प्राणितज, साबरकांठा, गुजरात-383305" द्वारा चलाई जा रही "राणासेन-हरसोल-साबरकांठा में शिक्षण और बाल गतिविधि हाल/अहाता दीवार का निर्माण, उपस्कर वाहन, साज-सामान और अंजिल अस्पताल, टी.बी. केंद्र और बच्चों और शैक्षणिक गतिविधयों को चलाने" की परियोजना अथवा स्कीम को 25.00 लाख रूपये की कॉपर्स निधि सिहत 571.00 लाख रूपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अविध अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 और 2017-18 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 168/2015 /फा. सं. वी-27015/2/2015-एस ओ (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th July, 2015

**S.O. 1955(E).**—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.591(E) dated the 20<sup>th</sup> August, 1997, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 2, "Construction of Tutorial and Children activity hall/Compound Wall, equipments, vehicle, furnishing and running of Anjali Hospital, T.B. Centre and Children and Educational Activities at Ranasan-Harsol-Sabarkantha, Gujarat" by "ANJALI (Society for Rural Health and Development), Post – Ranasan, Via Harsol, Taluka – Prantij, Sabarkantha, Gujarat – 383305" as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1998-1999 which was extended further vide notification number S.O.872(E) dated the 21<sup>st</sup> September, 2000 for a period of three years beginning with assessment year 2001-2002, which was extended further vide notification number S.O.350(E) dated the 31<sup>st</sup> March, 2003 for a period of three years beginning with assessment year 2004-2005; which was extended further vide notification number S.O.1003(E) dated the 5<sup>th</sup> July, 2006 for a period of three years beginning with financial year 2009-10 and which was further extended vide notification number S.O No.241(E) dated 21<sup>st</sup> January, 2009 for a period of three years beginning with financial year 2009-10 and which was further extended vide notification number S.O No.1092(E) dated 14<sup>th</sup> May, 2012 for a period of three years beginning with financial year 2012-13;

And whereas by notification number S.O.1003(E) dated the 5<sup>th</sup> July, 2006 the estimated cost was enhanced from Rs. 33.00 lakh plus a corpus fund of Rs.25.00 lakh to Rs.171.00 lakh including a corpus fund of Rs.25.00 lakh and vide notification number S.O. 1140(E) dated 18<sup>th</sup> May, 2010, the project cost was enhanced from Rs. 171 lakh including a corpus funds of Rs. 25 lakh to Rs. 571 lakh including a corpus fund of Rs. 25 lakh;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond eighteen years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Construction of Tutorial and Children activity hall/Compound Wall, equipments, vehicle, furnishing and running of Anjali Hospital, T.B. Centre and Children and Educational Activities at Ranasan-Harsol-Sabarkantha, Gujarat" which is being carried out by "ANJALI (Society for Rural Health and Development), Post – Ranasan, Via Harsol, Taluka – Prantij, Sabarkantha, Gujarat – 383305", without any change in the approved cost of Rs. 571 lakh including a corpus fund of Rs. 25 lakh, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with the financial year 2015-16 i.e. 2015-16, 2016-17 and 2017-18.

[No. 168/2015/ F. No. V.27015/2/2015-SO(NAT.COM)] MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2015

का.आ. 1956(अ).—जबिक आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 15.02.2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 243(अ.) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "केयर इंडिया मेडिकल सोसाइटी, एच-1/13, सालुंके विहार, पुणे-411048 (महाराष्ट्र)" द्वारा "विश्रान्ति क्रिटिकल कैंसर पैल्लिएटिव केयर सेंटर" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2006-07 को आरंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 5 पर अधिसूचित किया था ; जिसे बाद में दिनांक 25.03.2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 852(अ.) द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ; और जिसे बाद में दिनांक 09.10.2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 2414(अ.) द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 को आरंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ;

और जबिक उक्त परियोजना या स्कीम के नौं वर्षों से अधिक चलने की संभावना है :

और जबिक सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड. के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अविध के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है:

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा "केयर इंडिया मेडिकल सोसाइटी, एच-1/13, सालुंके विहार, पुणे-411048 (महाराष्ट्र)" द्वारा चलाई जा रही "विश्रान्ति क्रिटिकल कैंसर पैल्लिएटिव केयर सेंटर" की परियोजना अथवा स्कीम को 6.69 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अविध अर्थात 2015-16, 2016-17 और 2017-2018 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 169/2015 /फा. सं. वी-27015/2/2015-एस ओ (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2015

**S.O. 1956(E).**—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 234(E) dated the 15th February, 2007, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 5, "Vishranti critical cancer palliative care centre" by "Care India Medical Society, H-1/13, Salunke Vihar, Pune – 411048 (Maharashtra)", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2006-2007; which was extended further vide notification number S.O. 852 (E) dated 25th March, 2009 for a period of three years beginning with the financial year 2009-10 and which was extended further vide notification number S.O. 2414 (E) dated 9th October, 2012 for a period of three years beginning with the financial year 2014-15;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond nine years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Vishranti critical cancer palliative care centre" which is being carried out by Care India Medical Society, H-

1/13, Salunke Vihar, Pune – 411048 (Maharashtra)", without any change in the approved cost of Rs. 6.69 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial year 2015-16 i.e. 2015-16, 2016-17 and 2017-18.

[No. 169/2015/ F. No. V.27015/2/2015-SO(NAT.COM)] MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2015

का.आ. 1957(अ).—जबिक आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 07.05.2012 की अधिस्चना सं. का.आ. 1030(अ.) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "रामकृष्ण मिशन स्टूडेंस होम, सं. 66, सर पी. एस. शिवस्वामी सलई, मईलापुर, चेन्नई-600004" द्वारा "सुविधाविहीन छात्रों के लिए नि:शुल्क तकनीकी डिप्लोमा शिक्षण, छात्रावास प्रदान करना" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए 17 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 10 पर अधिस्चित किया था;

और जबिक उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबिक सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अविध के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा 'रामकृष्ण मिशन स्टूडेंस होम, सं. 66, सर पी. एस. शिवस्वामी सलई, मईलापुर, चेन्नई-600004" द्वारा चलाई जा रही "सुविधाविहीन छात्रों के लिए नि:शुल्क तकनीकी डिप्लोमा शिक्षण, छात्रावास प्रदान करना" की परियोजना अथवा स्कीम को 17.00 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अविध अर्थात 2015-16, 2016-17 और 2017-2018 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 170/2015 /फा. सं. वी-27015/2/2015-एस ओ (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2015

**S.O. 1957(E).**—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1030(E) dated 7.5.2012 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 10, "To provide free technical diploma education, boarding and lodging to the under privileged boys" by "Ramakrishna Mission Students' Home, No. 66, Sir P.S.Sivaswamy Salai, Mylapore, Chennai – 600 004", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 17 crore for a period of three years ending with financial year 2014-15;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "To provide free technical diploma education, boarding and lodging to the under privileged boys", which is

being carried out by "Ramakrishna Mission Students' Home, No. 66, Sir P.S.Sivaswamy Salai, Mylapore, Chennai – 600 004", without any change in the approved cost of Rs 17.00 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2015-16 i.e 2015-16, 2016-17 & 2017-18.

[No. 1/2015/ F. No. V.27015/2/2015-SO(NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2015

का.आ. 1958(अ).—जबिक आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 11.05.2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 1052(अ.) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "उडावुम करांगल, सं.460, एन. एस. के. नगर, आरंबक्कम, चेन्नई-600106, तिमलनाडु" द्वारा "अनाथ और निराश्रितों के पुनर्वास" की परियोजना को निर्धारण वर्ष 2010-11 को आरंभ होने वाली दो वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए 11.97 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 11 पर अधिसूचित किया था और जिसे बाद में दिनांक 16.03.2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 465(अ.) द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था।

और जबिक दिनांक 17.10.2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 3155(अ.) द्वारा अनुमानित लागत को 11.97 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 28.26 करोड़ रुपए कर दिया गया था ;

और जबिक उक्त परियोजना या स्कीम के पांच वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबिक सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अविध के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा "उडावुम करांगल, सं.460, एन. एस. के. नगर, आरंबक्कम, चेन्नई-600106, तमिलनाडु" द्वारा चलाई जा रही "अनाथ और निराश्रितों के पुनर्वास" की परियोजना अथवा स्कीम को 28.26 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अविध अर्थात 2015-16, 2016-17 और 2017-2018 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 171/2015 /फा. सं. वी-27015/2/2015-एस ओ (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th July, 2015

**S.O. 1958(E).**—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O. No.1052(E) dated 11th May, 2010, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 11 for "Rehabilitation of orphans and destitute" by "Udavum Karangal, No.460, N.S.K. Nagar, Arumbakkam, Chennai 600 106, Tamilnadu", at an estimated cost of Rs.11.97 crore, as an eligible project or scheme for a period of two financial years beginning with assessment year, 2010-11 and which was extended further vide notification number S.O. No. 465 (E) dated 16th March, 2012, for a period of three years ending with financial year 2014-15.

And whereas by notification number S.O. 3155(E) dated 17.10.2013 the estimated cost was enhanced from Rs. 11.97 crore to Rs. 28.26 crore;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond five years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Rehabilitation of orphans and destitute" which is being carried out by "Udavum Karangal, No.460, N.S.K. Nagar, Arumbakkam, Chennai 600 106, Tamilnadu", without any change in the approved cost of Rs. 28.26 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with the financial year 2015-16 i.e 2015-16, 2016-17 & 2017-18.

[No. 171 /2015/ F. No. V.27015/2/2015-SO (NAT.COM)] MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2015

का.आ. 1959(अ).—जबिक आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 18 नवंबर, 1999 की अधिस्चना सं. का.आ. 1140(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "श्रीकाकुलम व्योधिकुला संगम, (श्रीकाकुलम एल्डर्स एसोसिएशन), डी.सं.7-6-44, बुर्रावारी थोटा, श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश-532001" द्वारा "श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश में वृद्धाश्रम परिसर हेतु बिल्डिंग का निर्माण" की परियोजना को निर्धारण वर्ष 2000-2001 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 3 पर विनिर्दिष्ट किया था; जिसे बाद में दिनांक 10 सितंबर, 2002 की अधिस्चना सं. का.आ. 975(अ) के तहत निर्धारण वर्ष 2003-2004 को प्रारंभ होने वाली दो वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 23 अक्तूबर, 2005 की अधिस्चना सं. का.आ. 388(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-05 को प्रारंभ होने वाली दो वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 7 सितंबर, 2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 1503(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 6 अगस्त, 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 2056(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 14 मई, 2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 1072(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबिक दिनांक 9 मई, 2003 की अधिसूचना सं. का.आ. 529(अ) द्वारा अनुमानित लागत को 15 लाख रूपए की कॉर्पस निधि सिहत 23.93 लाख रू0 से बढ़ाकर 23.93 लाख रू0 कर दिया गया था; जिसे दिनांक 23 मार्च, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 388(अ) द्वारा अनुमानित लागत को 15.00 लाख रूपए की कार्पस निधि सिहत 23.93 लाख रू0 से बढ़ाकर 20.00 लाख रूपए की कॉर्पस निधि सिहत 23.93 लाख रू0 कर दिया गया था और दिनांक 6 अगस्त, 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 2056(अ.) द्वारा अनुमानित लागत को 20 लाख रूपए की कार्पस निधि सिहत 23.93 से बढ़ाकर 20 लाख रूपए की कार्पस निधि सिहत 30 लाख रूपए कर दिया गया था।

और जबिक उकत परियोजना या सकीम के 16 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबिक परियोजना लागत को बिल्डिंग के निर्माण हेतु 20 लाख रूपए की कॉर्पस निधि सहित 30 लाख रूपए से 40 लाख रूपए की कॉर्पस निधि सहित 60 लाख रूपए तक बढ़ाए जाने की संभावना है।

और जबिक सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 इ के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अविध के लिए विनिर्दिष्ट करने और परियोजना लागत को बिल्डिंग के निर्माण हेतु 20 लाख रूपए की कॉर्पस निधि सिहत 30 लाख रूपए से 40 लाख रूपए की कार्पस निधि सिहत 60 लाख रूपए तक संशोधित करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा "श्रीकाकुलम व्योधिकुला संगम, (श्रीकाकुलम एल्डर्स एसोसिएशन) डी.सं.7-6-44, बुर्रावारी थोटा, श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश-532001" द्वारा चलाई जा रही "श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश में वृद्धाश्रम परिसर हेतु बिल्डिंग का निर्माण" की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अविध अर्थात 2015-16, 2016-2017 और 2017-18 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है और;

(ख) दिनांक **18** नवंबर, 1999 की उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 1140(अ.) को निम्नलिखित आशय के लिए और आगे संशोधित करती है नामत:-

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 3 के सामने तालिका में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 कग के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाने वाली लागत की अधिकतम राशि से संबंधित कालम (4) में "बिल्डिंग के निर्माण हेतु 20 लाख रूपए की कॉर्पस निधि सहित 30 लाख रूपए" अक्षरों, अंकों और शबदों को "बिल्डिंग के निर्माण हेतु 40 लाख रूपए की कॉर्पस निधि सहित 60 लाख रूपए" अक्षरों, अंकों और शबदों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[सं. 172/2015 /फा. सं. वी-27015/2/2015-एस ओ (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2015

**S.O. 1959(E).**—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.1140(E) dated the 18th November, 1999, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 3, "Construction of building for old age home complex at Srikakulam, Andhra Pradesh" by "Srikakulam Vayodhikula Sangham, (Srikakulam Elders Association), D.No. 7-6-44, Burravari Thota, Srikakulam, Andhra Pradesh-532001", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2000-2001, which was extended further vide notification number S.O.975(E) dated the 10th September, 2002 for a period of two years beginning with assessment year 2003-2004, which was extended further vide notification number S.O.388(E) dated the 23rd October, 2005 for a period of two years beginning with financial year 2004-2005, which was extended further vide notification number S.O. 1503(E) dated the 7th September, 2007 for a period of three years beginning with financial year 2006-2007, which was extended further vide notification number S.O. 2056(E) dated 6th August, 2009 for a period of three years beginning with financial year 2009-10 and which was extended further vide notification number S.O. 1072(E) dated 14th May, 2012 for a period of three years ending with financial year 2014-15;

And whereas by notification number S.O.529(E) dated the 9th May, 2003, the estimated cost was enhanced from Rs.23.93 lakh to Rs.23.93 lakh plus a corpus fund of Rs.15.00 lakh and vide notification no.388(E) dated the 23rd March 2005 the estimated cost was further enhanced from Rs.23.93 lakh plus a corpus fund of Rs.15.00 lakh to Rs.23.93 lakh plus a corpus fund of Rs.20.00 lakh and vide notification number S.O. 2056(E) dated 6th August, 2009 the estimated cost was further enhanced from Rs. 23.93 lakh plus a corpus fund of Rs. 20 lakh to Rs. 30 lakh plus a corpus fund of Rs. 20 lakh;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond sixteen years;

And whereas the project cost is likely to enhance from Rs. 30 lakhs for construction of building plus a Corpus Fund of Rs. 20 lakhs to Rs. 60 lakhs for construction of building plus a Corpus Fund of Rs. 40 lakhs;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years and amending the project cost from Rs. 30 lakhs for construction of building plus a Corpus Fund of Rs.20 lakhs to Rs. 60 lakhs for construction of building plus a Corpus Fund of Rs.40 lakhs;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by subsection (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (a) hereby notifies the scheme or project "Construction of building for old age home complex at Srikakulam, Andhra Pradesh", which is being carried out by "Srikakulam Vayodhikula Sangham, (Srikakulam Elders Association), D.No.7-6-44, Burravari Thota,

Srikakulam, Andhra Pradesh-532001", as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with financial year 2015-16 i.e. 2015-16, 2016-17 and 2017-18 and;

(b) further amends the said notification number S.O. 1140(E) dated the 18th November, 1999, to the following effect, namely:-

In the said notification, in the Table against serial number 3, in column (4), relating to maximum to be allowed as deduction under section 35AC of Income Tax Act, 1961, for the letters, figures and word "Rs. 30 lakhs for construction of building plus a Corpus Fund of Rs.20 lakhs" the letters, figures and word "Rs. 60 lakhs for construction of building plus a Corpus Fund of Rs.40 lakhs" shall be substituted.

[No. 172/2015/ F. No. V.27015/2/2015-SO (NAT.COM)] MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2015

का.आ. 1960(अ).—जबिक आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 19.03.2005 की अधिस्चना सं. का.आ. 373(अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने "एसीआईएल नवासर्जन ग्रामीण विकास फाउंडेशन (आनाआरडे फाउंडेशन), मार्फत एजिस लॉजिसटिक्स लि0, चौथा तल, बालडोटा भवन, 117, एम.के. रोड, मुम्बई-400020" द्वारा "संसाधनों के उपयोग से ग्रामीण क्षेत्रों के समाजिक-आर्थिक विकास, गरीबों के लिए आय का सृजन, बंजरभूमि और प्रबंधन तथा नेटवर्किंग और लिंकेज" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2003-2004 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 6 पर अधिसूचित किया था; जिसे आगे दिनांक 26.10.2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1828(अ) द्वारा वितीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; जिसे आगे दिनांक 06.08.2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 2045(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-2010 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; और जिसे आगे दिनांक 14.05.2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 1081(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-2015 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए और अगे बढ़ा दिया गया था;

और जबिक दिनांक 14.05.2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 1081(अ) द्वारा अनुमानित लागत को 10.00 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 13.04 करोड़ रुपये कर दिया गया था;

और जबिक उक्त परियोजना अथवा स्कीम के बारह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबिक सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे तीन वर्षों की अविध के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है।

इसलिए, अब, केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा, (क) "एसीआईएल नवासर्जन ग्रामीण विकास फाउंडेशन(आनाआरडे फाउंडेशन), मार्फत एजिस लॉजिसटिक्स लि0, चौथा तल, बालडोटा भवन, 117, एम.के. रोड, मुम्बई-400020" द्वारा चलाई जा रही "संसाधनों के उपयोग से ग्रामीण क्षेत्रों के समाजिक-आर्थिक विकास, गरीबों के लिए आय का सृजन, बंजरभूमि और प्रबंधन तथा नेटवर्किंग और लिंकेज" की परियोजना को, 13.04 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना, वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अविध अर्थात 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 1**73**/2015/फा. सं. वी-27015/2/2015-एस ओ (रा.स.)] मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

New Delhi, the 20th July, 2015

**S.O. 1960(E).**— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.373(E) dated the 19th March, 2004, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 6, "Socio-Economic development of rural areas through leveraging of resources income generation for poor, wasteland & management and networking and linkages" by "ACIL Navasarjan Rural Development Foundation (AnaRDe Foundation), C/o Aegis Logistics Ltd., 4th Floor, Baldota Bhavan, 117, M.K. Road, Mumbai – 400020", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2003-2004, which was extended further vide notification number S.O. 1828(E) dated the 26th October, 2006 for a period of three years beginning with financial year 2006-2007; which was extended further vide notification S.O. No.2045(E) dated 6th August, 2009 for a period of three years beginning with the financial year 2009-10 and which was extended further vide notification S.O. No.1081(E) dated 14th May, 2012 for a period of three years beginning with the financial year 2014-15;

And whereas by notification number S.O. 1081(E) dated 14th May, 2012 the estimated cost was enhanced from Rs.10.00 crore to Rs. 13.04 crore;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond twelve years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (a) hereby notifies the scheme or project "Socio-Economic development of rural areas through leveraging of resources income generation for poor, wasteland & management and networking and linkages" which is being carried out by "ACIL Navasarjan Rural Development Foundation (AnaRDe Foundation), C/o Aegis Logistics Ltd., 4th Floor, Baldota Bhavan, 117, M.K. Road, Mumbai – 400020", without any change in the approved cost of Rs. Rs. 13.04 crore as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial year 2015-16 i.e 2015-16, 2016-17 & 2017-18.

[No. 173/2015/ F. No. V.27015/2/2015-SO(NAT.COM)] MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2015

का.आ. 1961(अ).—जबिक आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 21 सितंबर, 2000 की अधिसूचना सं. का.आ. 850(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "गुजरात कैंसर सोसायटी, न्यू सिविल हॉस्पिटल कैंपस, असरवा, अहमदाबाद-380016, गुजरात में कैंसर के मरीजों के मुफ्त इलाज की परियोजना" की परियोजना को निर्धारण वर्ष 2001-2002 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अविध के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 1 पर विनिर्दिष्ट किया था; जिसे बाद में दिनांक 30 अक्तूबर, 2003 की अधिसूचना सं. का.आ. 1249(अ) के तहत निर्धारण वर्ष 2004-2005 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 26 अक्तूबर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1840(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 6 अगस्त, 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 2041(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 14 मई, 2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 1095(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबिक दिनांक 16 जुलाई, 2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 1146(अ) द्वारा अनुमानित लागत को 611.00 लाख रूं। से बढ़ाकर 860.00 लाख रूं। कर दिया गया था; और जिसे दिनांक 6 अगस्त, 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 2041(अ) द्वारा अनुमानित लागत को 860.00 लाख रूं। से बढ़ाकर 1110 लाख रूं। कर दिया गया था।

और जबिक उक्त परियोजना या सुकीम के 15 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबिक परियोजना लागत को 1110 लाख रूपए से 1360 लाख रूपए तक बढ़ाए जाने की संभावना है।

और जबिक सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 इ के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अविध के लिए बढ़ाने और परियोजना लागत को 1110 लाख रूपए से 1360 लाख रूपए तक संशोधित करने की सिफारिश की है:

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा "गुजरात कैंसर सोसायटी, न्यू सिविल हॉस्पिटल कैंपस, असरवा, अहमदाबाद-380016, गुजरात" द्वारा चलाई जा रही "न्यू सिविल हॉस्पिटल कैंपस, असरवा, अहमदाबाद-380016, गुजरात में कैंसर के मरीजों के मुफ्त इलाज की परियोजना" की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अविध अर्थात 2015-16, 2016-2017 और 2017-18 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है;

(ख) दिनांक **2**1 सितंबर, 2000 की उक्त अधिसूचना सं. का.आ. **850**(अ.) को निम्नलिखित आशय के लिए और आगे संशोधित करती है नामत:-

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 1 के सामने तालिका में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35कग के तहत कटौती के रूप में अनुमित दी जाने वाली लागत की अधिकतम राशि से संबंधित कालम (4) में "1110 लाख रूपये" अक्षरों, अंकों और शबदों को "1360 लाख रूपये" अक्षरों, अंकों और शबदों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[सं. 174/2015/फा. सं. वी-27015/2/2015-एस ओ (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th July, 2015

**S.O. 1961(E).**— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.850(E) dated the 21st September, 2000, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 1, "Project for free treatment for cancer patients at New Civil Hospital Campus, Asarwa, Ahmedabad-380016, Gujarat" by "The Gujarat Cancer Society, New Civil Hospital Campus, Asarwa, Ahmedabad-380 016, Gujarat", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2001-2002, which was extended further vide notification number S.O.1249(E) dated the 30th October, 2003 for a period of three years beginning with assessment year 2004-2005; which was extended further vide notification number S.O.1840(E) dated the 26th October, 2006 for a period of three years beginning with financial year 2006-2007; which was extended further vide notification S.O.No. 2041(E) dated 6th August, 2009 for a period of three years beginning with the financial year 2009-10 and which was extended further vide notification S.O.No. 1095(E) dated 14th May, 2012 for a period of three years beginning with the financial year 2014-15;

And whereas by notification number S.O.1146(E) dated the 16th July, 2007 the estimated cost was enhanced from Rs.611.00 lakh to Rs. 860.00 lakh and vide notification number S.O.2041(E) dated 6th August, 2009 the estimated cost was further enhanced from Rs. 860.00 lakh to Rs. 1110 lakh.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond fifteen years;

And whereas the project cost is likely to enhance from Rs. 1110 lakh to Rs. 1360 lakh;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years and amending the project cost from Rs. 1110 lakh to Rs. 1360 lakh;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), - (a) hereby notifies the scheme or project "Project for free treatment for cancer patients at New Civil Hospital Campus, Asarwa, Ahmedabad-380016, Gujarat", which is being carried out by "The Gujarat Cancer Society, New Civil Hospital Campus, Asarwa,

Ahmedabad-380 016", as an eligible project or Scheme for a further period of three years beginning with the financial year 2015-16 i.e. 2015-16, 2016-17 and 2017-18;

(b) further amends the said notification number S.O. 850(E) dated the 21st September, 2000, to the following effect, namely:-

In the said notification, in the Table against serial number 1, in column (4), relating to maximum to be allowed as deduction under section 35AC of Income Tax Act, 1961, for the letters, figures and word "Rs. 1110 lakh" the letters, figures and word "Rs. 1360 lakh" shall be substituted.

[No. 174/2015/ F. No. V-27015/2/2015-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2015

का.आ. 1962(अ).— जबिक आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 13 मार्च, 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 737(अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने "स्कूल फार डीफ म्यूटस सोसायटी, आश्रम रोड अहमदाबाद-380009" द्वारा " नेत्रहीनों के लिए फिजियोथेरेपी कोर्स" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2011-2012 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 67.81 लाख रूपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 11 पर अधिसूचित किया था और जिसे बाद में दिनांक 17 अक्टूबर, 2013 की अधिसूचना स0 का0 आ0 3131(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढा दिया गया था।

और जबिक उक्त परियोजना अथवा स्कीम को छः वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबिक सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे तीन वर्षों की अविध के लिए करने की सिफारिश की है।

इसलिए, अब, केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा, "स्कूल फार डीफ म्यूटस सोसायटी, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009" द्वारा चलाई जा रही "नेत्रहीनों के लिए फिजियोथेरेपी कोर्स" परियोजना को 67.81 लाख रूपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अविध अर्थात् 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 175/2015/फा. सं. वी-27015/2/2015-एस ओ (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th July, 2015

**S.O. 1962(E).**—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 737 (E) dated 13th March, 2009 issued under clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 11 "Physiotherapy course for the blind" by "School for Deaf Mutes Society, Ashram Road, Ahmedabad- 380009", as an eligible project at the estimated cost of Rs.67.81 lakh for a period of three years ending with financial year 2011-12 and which was extended further vide notification No. S.O. 3131(E) dated 17th October, 2013 for a period of three years beginning with the financial year 2014-15.

And whereas the said project or Scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or Scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or Scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Physiotherapy course for the blind" which is being carried out by "School for Deaf Mutes Society, Ashram Road, Ahmedabad- 380009", without any change in the approved cost of Rs.67.81 lakh, as an eligible project or scheme, for a further period of three years commencing with financial year 2015-16 i.e. 2015-16, 2016-17 and 2017-18

[No. 175/2015/ F. No. V.27015/2/2015-SO(NAT.COM)] MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2015

का.आ. 1963(अ).—जबिक आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित् उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 8 अगस्त 2005 की अधिस्चना सं. का.आ. 1111(अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने "ब्लाइंड वेलफेयर काउंसिल, मिशन रोड नजदीक रेलवे ओवर ब्रिज, पो.बा.न.115, दाहोद-389151,गुजरात" द्वारा "सभी श्रेणियों के शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की शिक्षा, पुनर्वास, प्रशिक्षण तथा कल्याण हेतु भवनों का निर्माण" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2005-2006 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 6 पर अधिस्चित किया था; जिसे आगे दिनांक 18 मार्च, 2009 की अधिस्चना सं. का.आ. 762(अ.) द्वारा वितीय वर्ष 2008-2009 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था और जिसे आगे दिनांक 11 अगस्त, 2011 की अधिस्चना सं. का.आ. 1877(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-2012 से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए और ठागे बढ़ा दिया गया था और जिसे वाली तीन वर्षों की अविध के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबिक उक्त परियोजना अथवा स्कीम के नौ वर्षों से अधिक चलने की संभावना है।

और जबिक सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे तीन वर्षों की अविध के लिए चलाये जाने की सिफारिश की है।

इसलिए, अब, केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा, "ब्लाइंड वेलफेयर काउंसिल, मिशन रोड नजदीक रेलवे ओवर ब्रिज, पो.बा.न.115, दाहोद-389151, गुजरात" द्वारा चलाई जा रही "सभी श्रेणियों के शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की शिक्षा, पुनर्वास, प्रशिक्षण तथा कल्याण हेतु भवनों का निर्माण" की परियोजना को 5.73 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना, वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अविध अर्थात् 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है। चूंकि वित्तीय वर्ष 2014-15 पहले ही समाप्त हो गया है, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 क ग के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु कोई प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

[सं. 176/2015/फा. सं. वी-27015/2/2015-एस ओ (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

New Delhi, the 20th July, 2015

**S.O. 1963(E).**—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.1111(E) dated the 8th August, 2005, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 6, "Construction of buildings for the education, rehabilitation, training and welfare of persons with disabilities of all categories" by "Blind Welfare Council, Mission Road, Near Railway Overbridge, PO Box No.115, Dahod – 389151, Gujarat", as an eligible project or Scheme for a period of three years beginning with financial year 2005-2006; which was extended further vide notification number S.O.762(E) dated 18th March, 2009 for a further period of three years beginning with the financial year 2008-09 and which was extended further vide notification number S.O.1877(E) dated 11th August, 2011 for a further period of three years beginning with the financial year 2011-12;

And whereas the said project or Scheme is likely to extend beyond nine years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or Scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or Scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the Scheme or project "Construction of buildings for the education, rehabilitation, training and welfare of persons with disabilities of all categories" being carried out by "Blind Welfare Council, Mission Road, Near Railway Overbridge, PO Box No.115, Dahod – 389151, Gujarat", without any change in the approved cost of Rs.5.73 crore, as an eligible project or Scheme for a further period of three years beginning with financial year 2014-15 ie. financial year 2014-15, 2015-16 and 2016-17. Since the financial year 2014-15 has already lapsed, no certificate under section 35AC of the IT Act, 1961 would be issued for the financial years 2014-15.

[No. 176/2015/ F. No. V.27015/2/2015-SO (NAT.COM)] MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2015

का.आ. 1964(अ).—जबिक आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 15 फरवरी 2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 234(अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने "श्रीमती पारसनबेन नारनदास रामजी शाह (तालाज्वाला), सोसायटी फॉर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द डिसेब्लड, 51, विद्यानगर, भावनगर, गुजरात" द्वारा "वर्तमान गतिविधियों जैसे मुफ्त पोलियो अभियान; मोतियाबिन्द ऑपरेशन कैम्प का आयोजन आदि शारीरिक रूप से अक्षम गरीब लोगों को कार्यक्षम बनाने हेतु मुफ्त कृत्रिम अंगों को प्रदान कराना, का विस्तार करना तथा उन्हें सहयोग देना" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 8 पर अधिसूचित किया था; जिसे आगे दिनांक 08-05-2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 1255(अ) द्वारा वितीय वर्ष 2009-2010 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था और जिसे आगे दिनांक 14-05-2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 1068(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-2013 से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबिक दिनांक 14 मई, 2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 1068(अ) द्वारा अनुमानित लागत को 5**00.00** लाख रूपये से बढाकर 610**.00** लाख रूपये कर दिया गया था;

और जबिक उक्त परियोजना अथवा स्कीम को नौ वर्षों से अधिक बढ़ाए जाने की संभावना है;

और जबिक परियोजना लागत को 200 लाख रूपये की पुनर्वास कार्पस निधि सहित 610.00 लाख रूपये से बढाकर 810.00 लाख रूपये तक बढाए जाने की संभावना है।

और जबिक सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे तीन वर्षों की अविध के लिए विनिर्दिष्ट करने और परियोजना लागत को 200 लाख रूपये की पुनर्वास कार्पस निधि सहित 610.00 लाख रूपये से बढ़ाकर 810.00 लाख रूपये तक संशोधित करने की सिफारिश की है।

इसलिए, अब, केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा, "श्रीमती पारसनबेन नारनदास राम जी शाह (तालाज्वाला), सोसायटी फॉर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द डिसेब्लड, 51, विद्यानगर भावनगर गुजरात" द्वारा चलाई जा रही "वर्तमान गतिविधियों जैसे मुफ्त पोलियो अभियान; मोतियाबिन्द ऑपरेशन कैम्प का आयोजन आदि; शारीरिक रूप से अक्षम गरीब लोगों को कार्यक्षम बनाने हेतु मुफ्त कृत्रिम अंगों को प्रदान कराना, का विस्तार करना तथा उन्हें सहयोग देना" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है और;

(ख) उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 234(अ) दिनांक 15.02.2007 में निम्नलिखित प्रभाव हेतु संशोधन करती है, नामतः -

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम स0 8 के कॉलम (4) में, जोकि धारा 35 क ग के अन्तर्गत कटौती के रूप में अनुमत्य लागत की अधिकतम राशि से संबंधित है, में "610.00 लाख रूपये" अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों के स्थान पर "200 लाख रूपये की कार्पस निधि सहित 810.00 लाख रूपये" अक्षर, आंकड़े और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं. 177/2015/फा. सं. वी-27015/2/2015-एस ओ (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2015

**S.O. 1964(E).**— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 234(E) dated the 15th February, 2007, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 8, "Extension and support of present activities like conducting free polio operations; cataract operations camp etc.; providing free artificial limbs to rehabilitate orthopaedically disabled poor people" by "Smt. Parsanben Narandas Ramji Shah (Talajawala), Society for Relief & Rehabilitation of the disabled, 51, Vidyanagar, Bhavnagar, Gujarat", as an eligible project or Scheme for a period of three years beginning with financial year 2006-2007; which was extended further vide notification No. S.O. 1255 (E) dated 8th May, 2009 for a period of three years beginning with the financial year 2009-10 and which was extended further vide notification No. S.O. 1068 (E) dated 14th May, 2012 for a period of three years beginning with the financial year 2012-13;

And whereas by notification number S.O. 1068 (E) dated 14th May, 2012 the estimated cost was enhanced from Rs. 500.00 lakh to Rs.610.00 lakh;

And whereas the said project or Scheme is likely to extend beyond nine years;

And whereas the project cost is likely to enhance from Rs. 610.00 lakh to Rs. 810.00 lakh including rehabilitation Corpus fund of Rs. 200. Lakh;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or Scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or Scheme for a further period of three years and amending the project cost from Rs. 610.00 lakh to Rs. 810.00 lakh including rehabilitation Corpus fund of Rs. 200. Lakh.;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (a) hereby notifies the Scheme or project "Extension and support of present activities like conducting free polio operations; cataract operations camp etc.; providing free artificial limbs to rehabilitate orthopaedically disabled poor people" which is being carried out by "Smt. Parsanben Narandas Ramji Shah (Talajawala), Society for Relief & Rehabilitation of the

disabled, 51, Vidyanagar, Bhavnagar, Gujarat", as an eligible project or Scheme for a further period of three years beginning with financial year 2015-16 i.e. 2015-16, 2016-17 and 2017-18 and;

(b) further amends the said notification number S.O. 234(E) dated the 15th February, 2007, to the following effect, namely:-

In the said notification, in the Table against serial number 8, in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section of 35AC of Income Tax Act, 1961 for the letters, figures and word "Rs. 610.00 lakh" the letters, figures and word "Rs. 810.00 lakh including rehabilitation Corpus fund of Rs. 200. Lakh" shall be substituted.

[No. 177/2015/ F. No. V-27015/2/2015-SO(NAT.COM)] MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2015

का.आ. 1965(अ).—जबिक आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 6 अक्टूबर 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 2545(अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने "नाना पालकर स्मृति समिति रूग्ण सेवा सदन,158 रूग्ण सेवा सदन मार्ग, डॉ अम्बेडकर नगर, परेल, मुम्बई-400012" द्वारा "मैडिकल रोगियों के लिए नाना पालकर स्मृति समिति प्रोजेक्ट, मुम्बई" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2009-2010 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 6 पर अधिसूचित किया था और जिसे आगे दिनांक 14-05-2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 1079(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-2013 से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबिक उक्त परियोजना अथवा स्कीम को छ: वर्षों से अधिक चलने की संभावना है:

और जबिक सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे तीन वर्षों की अविध के लिए करने की सिफारिश की है।

इसलिए, अब, केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा, "नाना पालकर स्मृति समिति रूग्ण सेवा सदन,158 रूग्ण सेवा सदन मार्ग, डॉ अम्बेडकर नगर, परेल, मुम्बई -400012" द्वारा चलाई जा रही "मैडिकल रोगियों के लिए नाना पालकर स्मृति समिति प्रोजेक्ट, मुम्बई" की परियोजना को 9.71 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अविध अर्थात् 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 178/2015/फा. सं. वी-27015/2/2015-एस ओ (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th July, 2015

**S.O. 1965(E).**— Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2545 (E) dated 6th October, 2009, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 6, "Nana Palkar Smruti Samiti project for medical patients, Mumbai" by "Nana Palkar Smruti Samiti, Rugna Seva Sadan, 158 Rugna Seva Sadan Marg, Dr. Ambedkar Road, Parel, Mumbai 400012", as an eligible project or Scheme for a period of three years beginning with financial year 2009-10 and which was extended further vide notification S.O. No. 1079(E) dated 14th May, 2012 for a period of three years beginning with the financial year 2012-13;

And whereas the said project or Scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or Scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or Scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (a) hereby notifies the Scheme or project "Nana Palkar Smruti Samiti project for medical patients, Mumbai" which is being carried out by "Nana Palkar Smruti Samiti, Rugna Seva Sadan, 158 Rugna Seva Sadan Marg, Dr. Ambedkar Road, Parel, Mumbai 400012", without any change in the approved cost of Rs. 9.71 crore, as an eligible project or Scheme for a further period of three years commencing with the financial year 2015-16 i.e. 2015-16, 2016-17 and 2017-18.

 $[No.\ 178\ /2015/\ F.\ No.\ V.27015/2/2015\text{-SO(NAT.COM)}]$ 

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2015

का.आ. 1966(अ).—जबिक आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पिठत उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 7 जनवरी, 2004 की अधिसूचना सं. का.आ. 19(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन,, 18, कॉलेज रोड, चैन्ने-600006" द्वारा "आंखों की मुफ्त सर्जरी और अस्पताल को चलाने" की परियोजना को निर्धारण वर्ष 2004-05 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अविध के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 11 पर अधिसूचित किया था; जिसे बाद में दिनांक 4 सितंबर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1408(अ) के तहत वित्तीय वर्ष 2006-07 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 25 मार्च, 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 847(अ) के तहत वित्तीय वर्ष 2009-10 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 27 दिसंबर, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 2892(अ) के तहत वित्तीय वर्ष 2012-13 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए और बढ़ा दिया गया था; आर होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबिक दिनांक 27 दिसंबर, **2011** की अधिसूचना सं. का॰ आ॰ 2892(अ.) के द्वारा अनुमानित लागत को 28 करोड़ रूपए की कार्पस निधि सिहत 32.02 करोड़ रूपए से बढ़ाकर 52 करोड़ रूपए की कार्पस निधि सिहत 68.07 करोड़ रूपए कर दिया गया था;

और जबिक उक्त परियोजना या स्कीम के 12 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबिक सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय सिमिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस सिमिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अविध के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, "मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन,, 18, कॉलेज रोड, चैन्ने-600006" द्वारा चलाई जा रही "आंखों की मुफ्त सर्जरी और अस्पताल को चलाने" की परियोजना अथवा स्कीम को 52 करोड़ रूपए की कॉर्पस निधि सिहत 68.07 करोड़ रूपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2015-16, 2016-17 और 2017-2018 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 179/2015/फा. सं. वी-27015/2/2015-एस ओ (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

New Delhi, the 20th July, 2015

**S.O. 1966(E).**—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.19(E) dated the 7th January, 2004, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 11, "Free Eye surgeries and running of hospital" by "Medical Research Foundation, 18, College Road, Chennai–600006", as an eligible project or Scheme for a period of three years beginning with assessment year 2004-2005, which was extended further vide notification number S.O.1408(E) dated the 4th September, 2006 for a period of three years beginning with financial year 2006-2007, which was extended further vide notification number S.O. 847(E) dated 25th March, 2009 for a period of three years beginning with financial year 2009-10 and which was extended further vide notification number S.O. 2892(E) dated 27th December, 2011 for a period of three years beginning with financial year 2012-13;

And whereas by notification number S.O. 2892(E) dated 27th December, 2011 the estimated cost was enhanced from Rs. 32.70 crore including a corpus fund of Rs. 28 crore to Rs. 68.07 crore including a corpus fund of Rs. 52 crore;

And whereas the said project or Scheme is likely to extend beyond twelve years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or Scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or Scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the Scheme or project "Free Eye surgeries and running of hospital" which is being carried out by "Medical Research Foundation, 18, College Road, Chennai – 600006", without any change in the approved cost of Rs. 68.07 crore including a corpus fund of Rs. 52 crore as an eligible project or Scheme for a further period of three years beginning with financial year 2015-16 i.e. 2015-16, 2016-17 and 2017-18.

[No. 179/2015/ F. No. V.27015/2/2015-SO(NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2015

का.आ. 1967(अ).—जबिक आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 19 मई, 1997 की अधिस्चना सं. का.आ. 388(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "हेंडीकैप्ड चिल्ड्रन्स पेरेन्ट्स एसोशिएशन, प्लॉट नं0 k (प्लॉट नं०13 के पीछे), इन्स्टीट्यूशनल सेक्टर-5, द्वारका, नई दिल्ली-110045" द्वारा "मंदबुद्धियों के लिए गृह निर्माण, इसकी साज-सज्जा, इसके परिचालन तथा इसके लिए सहायक सामग्री/अनुप्रयोज्य सामग्री/उपस्कर तथा वाहन उपलब्ध कराने" की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1998-99 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 25 पर अधिस्चित किया था; जिसे बाद में दिनांक 28 मार्च, 2001 की अधिस्चना सं. का.आ. 290(अ) के तहत निर्धारण वर्ष 2001-02 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 23 फरवरी, 2004 की अधिस्चना सं. का.आ. 224(अ) के तहत निर्धारण वर्ष 2004-05 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 23 अक्तूबर, 2007 की अधिस्चना सं. का.आ. 1802(अ) के तहत वित्तीय वर्ष 2006-07 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 14 अक्तूबर, 2009 की अधिस्चना सं. का.आ. 2607(अ) के तहत वित्तीय वर्ष 2009-10 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 9 अक्तूबर, 2012 की अधिस्चना सं. का.आ. 2415(अ) के तहत वित्तीय वर्ष 2012-13 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबिक उक्त परियोजना या स्कीम के 18 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबिक सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अविध के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है:

इसिलए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, "हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन्स पेरेन्ट्स एसोशिएशन, प्लॉट नं0 k (प्लॉट नं013 के पीछे), इन्स्टीट्यूशनल सेक्टर-5, द्वारका, नई दिल्ली-110045" द्वारा चलाई जा रही "मंदबुद्धियों के लिए गृह निर्माण, इसकी साज-सज्जा, इसके परिचालन तथा इसके लिए सहायक सामग्री/अनुप्रयोज्य सामग्री/उपस्कर तथा वाहन उपलब्ध कराने" की परियोजना अथवा स्कीम को 100.00 लाख रूपए की कॉपर्स निधि सहित 245.00 लाख रूपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अविध अर्थात 2015-16, 2016-17 और 2017-2018 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 180/2015/फा. सं. वी-27015/2/2015-एस ओ (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th July, 2015

S.O. 1967(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.388(E) dated the 19th May, 1997, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 25, "Construction, aids/application/equipments, vans, furnishing and running of Home for spastics" by "Handicapped Children's Parents Association, Plot No.K (Behind Plot No.13), Institutional Sector-5, Dwarka, New Delhi – 110045", as an eligible project or Scheme for a period of three years beginning with assessment year 1998-1999, which was extended further vide notification number S.O.290(E) dated the 28th March, 2001 for a period of three years beginning with assessment year 2001-2002, which was extended further vide notification number S.O.1802(E) dated the 23rd October, 2007 for a period of three years beginning with financial year 2006-2007, which was extended further vide notification number S.O. 2607(E) dated 14th October, 2009 for a period of three years beginning with financial year 2009-10 and which was extended further vide notification number S.O. 2415(E) dated 9th October, 2012 for a period of three years beginning with financial year 20012-13;

And whereas the said project or Scheme is likely to extend beyond eighteen years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or Scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or Scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the Scheme or project "Construction, aids/application/equipments, vans, furnishing and running of Home for spastics" which is being carried out by "Handicapped Children's Parents Association, Plot No.K (Behind Plot No.13), Institutional Sector-5, Dwarka, New Delhi – 110045", without any change in the approved cost of Rs. 245.00 lakh including a corpus fund of Rs.100.00 lakh, as an eligible project or Scheme for a further period of three years beginning with financial 2015-16 i.e. 2015-16, 2016-17 and 2017-18.

[No. 180/2015/ F. No. V.27015/2/2015-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2015

का.आ. 1968(अ).—जबिक आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 07.05.2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 1030(अ.) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "मार पचोमिओस चेरिटेबल सोसायटी, मार पचोमिओस माउंट, मीमपारा डाकखाना पुथेनक्रूज, एर्णांकुलम-682308" द्वारा "(क) प्रसन्नम-मेंटल हेल्थ केयर सेंटर, केरिकोडु (डाकखाना), केरल (ख) प्रकासम-इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन साउथ पिरामाडोम, पंपाकुडा, एर्णांकुलम, केरल, (ग) प्रसनथम- एचआईवी/एड्स और कैंसर रोगियों के लिए पेलिएटिव केयर सेंटर" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए 11.49 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 8 पर अधिसूचित किया था;

और जबिक उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबिक सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अविध के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसिलए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पिठत उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिंक्यों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा "मार पचोमिओस चीरिटेबल सोसायटी, मार पचोमिओस माउंट, मीमपारा डाकखाना पुथेनक्रूज, एर्णाकुलम-682308" द्वारा चलाई जा रही "(क) प्रसन्नम-मेंटल हेल्थ केयर सेंटर, केरिकोडु (डाकखाना), केरल (ख) प्रकासम-इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन साउथ पिरामाडोम, पंपाकुडा, एर्णाकुलम, केरल, (ग) प्रसन्थम- एचआईवी/एड्स और कैंसर रोगियों के लिए पेलिएटिव केयर सेंटर" की परियोजना अथवा स्कीम को, 11.49 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना, वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अविध अर्थात् 2015-16, 2016-17 और 2017-2018 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 181/2015/फा. सं. वी-27015/2/2015-एस ओ (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th July, 2015

**S.O. 1968(E).**— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1030(E) dated 7.5.2012 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 8, "(a) PRASANNAM – Mental Health Care Centre, Karikodu (P.O.), Kerala (b) PRAKASAM – Institute of Special Education South Piramadom, Pampakuda, Ernakulam, Kerala. (c) PRASANTHAM – Palliative Care Centre for HIV/AIDS & Cancer Patients" by "Mar Pachomios Charitable Society, Mar Pachomios Mount, Meempara P.O.Puthencruze, Ernakulam – 682 308", as an eligible project or Scheme, at the estimated cost of Rs. 11.49 crore for a period of three years ending with financial year 2014-15;

And whereas the said project or Scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or Scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or Scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the Scheme or project "(a) PRASANNAM – Mental Health Care Centre, Karikodu (P.O.), Kerala (b) PRAKASAM – Institute of Special Education South Piramadom, Pampakuda, Ernakulam, Kerala. (c) PRASANTHAM – Palliative Care Centre for

HIV/AIDS & Cancer Patients", which is being carried out by "Mar Pachomios Charitable Society, Mar Pachomios Mount, Meempara P.O.Puthencruze, Ernakulam – 682 308", without any change in the approved cost of Rs 11.49 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2015-16 i.e. 2015-16, 2016-17 and 2017-18.

[No. 181/2015/ F. No. V.27015/2/2015-SO(NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2015

का.आ. 1969(अ).—जबिक आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 14.06.2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 1370(अ.) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "संत बाबा भाग सिंह मेमोरियल चेरिटेबल सोसायटी, डेरा संत पुरा, डाक्खाना मंको, जिला जालंधर, पंजाब-144106" द्वारा "संत बाबा भाग सिंह ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए 3495 लाख रुपए की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 23 पर अधिसूचित किया था;

और जबिक उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबिक सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अविध के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है:

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा "संत बाबा भाग सिंह मेमोरियल चेरिटेबल सोसायटी, डेरा संत पुरा, डाक्खाना मंको, जिला जालंधर, पंजाब-144106" द्वारा चलाई जा रही "संत बाबा भाग सिंह ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली" की परियोजना अथवा स्कीम को, 3495 लाख रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना, वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अविध अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है। चूँिक वित्तीय वर्ष 2014-15 पहले ही समाप्त हो गया है, इसलिए वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 क ग के तहत कोई प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा।

[सं. 182/2015/फा. सं. वी-27015/2/2015-एस ओ (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2015

**S.O. 1969(E).**— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1370(E) dated 14.6.2011 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 23, "Sant Baba Bhag Singh Rural Health Care System" by "Sant Baba Bhag Singh Memorial Charitable Society, Dera Sant Pura, PO Manko, District Jalandhar, Punjab 144106", as an eligible project or Scheme, at the estimated cost of Rs. 3495 lakh for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or Scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Sant Baba Bhag Singh Rural Health Care System", which is being carried out by "Sant Baba Bhag Singh

Memorial Charitable Society, Dera Sant Pura, PO Manko, District Jalandhar, Punjab 144106", without any change in the approved cost of Rs 3495 lakh, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, 2015-16 & 2016-17. Since the financial year 2014-15 has already lapsed, no certificate under section 35AC of the IT Act, 1961 would be issued for the financial years 2014-15.

[No. 182/2015/ F. No. V.27015/2/2015-SO(NAT.COM)] MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2015

का.आ. 1970(अ).—जबिक आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 28 दिसंबर, 2001 की अधिस्चना सं. का.आ. 1267(अ.) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "श्रीमती उषाबेन रिसकलाल शाह दिग्विजय लॉयन दार्दी सहायक ट्रस्ट, 5, विश्रांति गृह, सिविल अस्पताल के सामने, अहमदाबाद-380016" द्वारा "पूरे गुजरात में दार्दी सहायक ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं चलाने" की पिरयोजना को निर्धारण वर्ष 2001-2002 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए एक पात्र पिरयोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 1 पर अधिसूचित किया था, और जिसे बाद में दिनांक 05.07.2004 की अधिसूचना सं. का. आ. 783(अ.) के तहत वित्तीय वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाली दो वर्षों की अविध के लिए और बढ़ा दिया गया ; जिसे बाद में दिनांक 15.02.2007 की अधिसूचना सं. का. आ. 237(अ.) द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 से प्रारंभ होने वाली दो वर्षों की अविध के लिए और बढ़ा दिया गया था ; जिसे बाद में दिनांक 18.05.2009 की अधिसूचना सं. का. आ. 1254(अ.) द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए और बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 27.12.2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 2887(अ.) के तहत वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए और बढ़ा दिया गया था ;

और जबिक दिनांक 15.02.2007 की अधिसूचना सं. का. आ. 237(अ.) द्वारा अनुमानित लागत को 15.00 लाख रुपए की कार्पस निधि सिहत 51.00 लाख रुपए से 15.00 लाख रुपए की कार्पस निधि सिहत 102.00 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया था और जबिक दिनांक 27.02.2011 की अधिसूचना सं. का. आ. 2887(अ.) द्वारा अनुमानित लागत को 15 लाख रुपए की कार्पस निधि सिहत 102 लाख रुपए से 15 लाख रुपए की कार्पस निधि सिहत 171 लाख रुपए तक और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबिक उक्त परियोजना या स्कीम के तेरह वर्षों से अधिक तक चलने की संभावना है;

और जबिक सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्ष की अविध के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसिलए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, "श्रीमती उषाबेन रिमकताल शाह दिग्विजय लॉयन दार्दी सहायक ट्रस्ट, 5, विश्रांति गृह,सिविल अस्पताल के सामने, अहमदाबाद-380016" द्वारा चलाई जा रही "पूरे गुजरात में दार्दी सहायक ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं चलाने" की परियोजना अथवा स्कीम को 15 लाख रुपए की कार्पस निधि सिहत 171 लाख रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाली वर्ष से आगे तीन वर्षों की अविध अर्थात 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए और एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है और;

[सं. 183/2015/फा. सं. वी-27015/2/2015-एस ओ (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

New Delhi, the 20th July, 2015

**S.O. 1970(E).**— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.1267(E) dated the 28th December, 2001, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 1, "Running of free medical services by Dardi Sahayak Trust at whole of Gujarat" by "Smt. Ushaben Rasiklal Shaw Digvijay Lion Dardi Sahayak Trust, 5, Vishranti Gruh, Opp. Civil Hospital, Amedabad – 380016", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2001-2002, which was extended further vide notification number S.O.783(E) dated the 5th July, 2004 for a period of two years beginning with financial year 2004-2005, which was extended further vide notification number S.O.237(E) dated the 15th February, 2007 for a period of two years beginning with financial year 2007-2008, which was extended further vide notification number S.O.1254(E) dated 18th May, 2009 for a period of three years beginning with financial year 2009-10 and which was extended further vide notification number S.O. 2887(E) dated 27th December, 2011 for a period of three years beginning with financial year 2012-13;

And whereas by notification number S.O.237(E) dated the 15th February, 2007 the estimated cost was enhanced from Rs. 51.00 lakh including a corpus fund of Rs.15.00 lakh to Rs.102.00 lakh including a corpus fund of Rs.15.00 lakh and whereas by notification number S.O. 2887(E) dated 27th December, 2011 the estimated cost was further enhanced from Rs.102 lakh including corpus fund of Rs. 15 lakh to Rs. 171 lakh including a corpus fund of Rs. 15 lakh;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond thirteen years;

And, whereas, the National Committee for the Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Running of free medical services by Dardi Sahayak Trust at whole of Gujarat" which is being carried out by "Smt. Ushaben Rasiklal Shaw Digvijay Lion Dardi Sahayak Trust, 5, Vishranti Gruh, Opp. Civil Hospital, Amedabad – 380016", without any change in the approved cost of Rs. 171 lakh including a corpus fund of Rs. 15 lakh, for a further period of three years commencing with financial year 2015-16 i.e. 2015-16, 2016-17 and 2017-18.

[No. 183/2015/ F. No. V.27015/2/2015-SO(NAT.COM)] MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2015

का.आ. 1971(अ).—जबिक आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 3 अक्तूबर, 1997 की अधिसूचना सं. का.आ. 698(अ.) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "ग्लोबल हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, 102 ओम शान्ति, 48, स्वास्तिक सोसायटी, एन एस रोड सं. 3, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई-400003" द्वारा "माउंट आबू, जिला सिरोही, राजस्थान में जे वाटुमुल ग्लोबल अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के निर्माण और चलाने" की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1998-99 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 8 पर अधिसूचित किया था, और जिसे बाद में दिनांक 21.09.2000 की अधिसूचना सं. का.आ. 863(अ.) के तहत निर्धारण वर्ष 2001-2002 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया ; जिसे बाद में दिनांक 29.09.2003 की अधिसूचना सं. का.आ. 1126(अ.) द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-05 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ; जिसे बाद में दिनांक 15.02.2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 241(अ.) द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ; और जिसे बाद में दिनांक 25.03.2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 842(अ.) के तहत वित्तीय वर्ष 2009-10 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ; और जिसे बाद में दिनांक 14.05.2012 की

28

अधिसूचना सं. का.आ. 1085(अ.) के तहत वित्तीय वर्ष 2012-13 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ;

और जबिक दिनांक 15.02.2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 241(अ.) के द्वारा अनुमानित लागत को 500.00 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 61.27 लाख रुपए से 500.00 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 1361.27 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया था और जबिक दिनांक 14.05.2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 1085(अ.) द्वारा अनुमानित लागत को 500.00 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 1361.27 लाख रुपए से 500 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 3100.00 लाख रुपए तक और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबिक उक्त परियोजना या स्कीम के अठारह वर्षों से अधिक तक चलने की संभावना है ;

और जबिक सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "ग्लोबल हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, 102 ओम शान्ति, 48, स्वास्तिक सोसायटी, एनएस रोड सं. 3, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई-400003" द्वारा चलाई जा रही "माउंट आबू, जिला सिरोही, राजस्थान में जे वाद्मुल ग्लोबल अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के निर्माण और चलाने" की परियोजना अथवा स्कीम को 500.00 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 3100.00 लाख रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाली वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए और एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है और;

[सं. 184/2015/फा. सं. वी-27015/2/2015-एस ओ (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th July, 2015

S.O. 1971(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O.698(E) dated the 3rd October, 1997, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 8, "Construction and running of J.Watumull Global Hospital & Research Centre at Mount Abu, District Sirohi, Rajasthan", by "Global Hospital & Research Centre, 102, Om Shanti, 48, Swastik Society, N.S. Road No.3, Vile Parle (W), Mumbai-400003", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1998-1999, which was extended further vide notification number S.O.863(E) dated the 21st September, 2000 for a period of three years beginning with assessment year 2001-2002, which was extended further vide notification number S.O.1126(E) dated the 29th September, 2003 for a period of three years beginning with assessment year 2004-2005, which was extended further vide notification number S.O.241(E) dated the 15th February, 2007 for a period of three years beginning with financial year 2006-2007, which was extended further vide notification number S.O. 842(E) dated 25th March, 2009 for a period of three years beginning with financial year 2009-10 and which was extended further vide notification number S.O. 1085(E) dated 14th May, 2012 for a period of three years beginning with financial year 2012-13;

And whereas by notification number S.O.241(E) dated the 15th February, 2007 the estimated cost was enhanced from Rs.61.27 lakh plus a corpus fund of Rs. 500.00 lakh to Rs. 1361.27 lakh including a corpus fund of Rs.500.00 lakh and whereas by notification number S.O. 1085 (E) dated 14th May, 2012 2007 the estimated cost was further enhanced from Rs. 1361.27 lakh including a corpus of Rs. 500 lakh to Rs. 3100.00 lakh including a corpus of Rs. 500 lakh;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond eighteen years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (a) hereby notifies the scheme or project, "Construction and running of J.Watumull Global Hospital & Research Centre at Mount Abu, District Sirohi, Rajasthan" which is being carried out by "Global Hospital & Research Centre, 102, Om Shanti, 48, Swastik Society, N.S. Road No.3, Vile Parle (W), Mumbai-400003", as an eligible project or scheme without any change in the approved cost of Rs. 3100.00 lakh including a corpus of Rs. 500 lakh, for a further period of three years commencing with financial year 2015-16 i.e. 2015-16, 2016-17 and 2017-18.

[No. 184/2015/ F. No. V.27015/2/2015-SO(NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2015

का.आ. 1972(अ).—जबिक आयंकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 23 अक्तूबर, 2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 1794(अ.) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ''ट्यिक्त विकास केंद्र इंडिया, 19, 39वां ''ए'' क्रास, 11वां मेन, IV 'टी' ब्लाक, जयानगर, बंगलौर-560041'' द्वारा ''जनजातीय स्कूल और कल्याण पहलों'' की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2009-10 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में 6.42 करोड़ं रुपए की अनुमानित लागत पर क्रम सं. 10 पर अधिसूचित किया था, और जिसे बाद में दिनांक 29.09.2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 2358(अ) के तहत वित्तीय वर्ष 2012-2013 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए और बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 17.10.2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 3129(अ.) के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबिक दिनांक 29.09.2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 2358(अ.) द्वारा परियोजना लागत को 6.42 करोड़ रुपए से 11.51 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया था;

और जबिक परियोजना लागत के 11.51 करोड़ रुपए से 21.99 करोड़ रुपए तक बढ़ाने की संभावना है;

और जबिक सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 इ के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम की परियोजना लागत को अनुमोदित अविध अर्थात वित्तीय वर्ष 2015-16 तक के लिए 11.51 करोड़ रुपए से 21.99 करोड़ रुपए तक संशोधित करने की सिफारिश की है;

इसिलए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा दिनांक 23.10.2007 की उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 1794(अ) को निम्निलिखित आशय के लिए संशोधित करती है, नामत:-

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 10 के सामने तालिका में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत्य की जाने वाली अधिकतम राशि से संबंधित कालम (4) में ''11.51 करोड़ रुपए'' अक्षरों, अंकों और शब्दों को ''21.99 करोड़ रुपए'' अक्षरों, अंकों और शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[सं. 185/2015 /फा. सं. वी-27015/2/2015-एस ओ (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

New Delhi, the 20th July, 2015

**S.O. 1972(E).**— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) S.O 1794(E) dated 23.10.2007 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Incometax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 10 "Tribal Schools and Welfare Initiatives" by "Vyakti Vikas Kendra India, 19, 39th "A" Cross, 11th Main, IV 'T' Block, Jayanagar, Bangalore – 560 041", as an eligible project at the projected cost of Rs.6.42 crore for a period of three years ending with financial year 2009-2010, which was further extended vide S.O. No. 2358(E) dated 29.09.2010 for a period of three years ending with financial year 2012-13 and which was further extended vide S.O. No. 3129(E) dated 17.10.2013 for a period of three years ending with financial year 2015-16;

And whereas vide Notification S.O. No. 2358(E) dated 29.9.2010, the project cost was enhanced from Rs.6.42 crore to Rs.11.51 crore;

And whereas the project cost is likely to enhance from Rs.11.51 crore to Rs.21.99 crore;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for amending the project cost from Rs.11.51 crore to Rs.21.99 crore for the approved period i.e. upto financial years 2015-16;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961),- hereby amends the said notification number S.O. 1794(E) dated 23.10.2007, to the following effect, namely:-

In the said notification, in the Table against serial number 10, in column (4), relating to maximum to be allowed as deduction under section 35AC of Income Tax Act, 1961, for the letters, figures and word "Rs. 11.51 crore" the letters, figures and word "Rs.21.99 crore" shall be substituted.

[No. 185/2015/ F. No. V.27015/2/2015-SO(NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2015

का.आ. 1973(अ).—जबिक आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 17.10.1995 की अधिसूचना सं. का.आ. 844(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "निष्काम सिख वेलफेयर काउंसिल, बीएफ-33, टैगौर गार्डन, नई दिल्ली-110027" द्वारा "गांव खानपुर जिला रोपड़, पंजाब में माता गुजरी वृद्धागृह एवं अनाथालय को चलाने के लिए खर्च" की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1996-1997 से प्रारंभ होने वाली दो वर्ष की अविध के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 14 पर अधिसूचित किया था; और जिसे बाद में दिनांक 27.03.1997 की अधिसूचना सं. का.आ. 259(अ) के तहत निर्धारण वर्ष 1998-1999 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 20.09.2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 924(अ) द्वारा निर्धारण वर्ष 2001-02 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 23.06.2004 की अधिसूचना सं. का.आ. 724(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2003-04 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षी की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 29.03.2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 480(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 06.09.2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 2054(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 12.03.2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 666(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था:

और जबिक दिनांक 20 सितंबर, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 924(अ) द्वारा अनुमानित लागत को 27.36 लाख रू० से बढ़ाकर 99.00 लाख रू० कर दिया गया था; और जिसे दिनांक 23 जून, 2004 की अधिसूचना सं. का.आ. 724(अ) द्वारा अनुमानित लागत को 99.00 लाख रू० से बढ़ाकर 159.00 लाख रू० कर दिया गया था;

और जबिक उक्त परियोजना या स्कीम के 21 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबिक परियोजना लागत के 159.00 लाख रूपए से बढ़कर 350.00 लाख रूपए होने की संभावना है।

और जबिक सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अविध के लिए विनिर्दिष्ट करने और परियोजना लागत को 159 लाख रूपए से संशोधित करके 350 लाख रूपए करने की सिफारिश की है:

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा "निष्काम सिख वेलफेयर काउंसिल, बीएफ-33, टैगौर गार्डन, नई दिल्ली-110027" द्वारा चलाई जा रही "गांव खानपुर जिला रोपड़, पंजाब में माता गुजरी वृद्धागृह एवं अनाथालय को चलाने के लिए खर्च" की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अविध अर्थात 2015-16, 2016-2017 और 2017-18 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है और;

(ख) दिनांक 17 अक्तूबर, 1995 की उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 844(अ.) को निम्नलिखित आशय के लिए और आगे संशोधित करती है नामत:-

उक्त अधिसूचना सारणी में, क्रम सं. 14 के कॉलम (4) में जोकि धारा 35कग के तहत कटौती के रूप में अनुमित दी जाने वाली लागत की अधिकतम राशि से संबंधित है, में "159.00 लाख रूपये" अक्षरों, अंकों और शब्दों को "350.00 लाख रूपये" अक्षरों, अंकों और शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[सं. 186/2015 /फा. सं. वी-27015/2/2015-एस ओ (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2015

**S.O. 1973(E).**— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O.844(E) dated the 17th October, 1995, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 14, "Running expenses for Mata Gujari Old Age Home-cum-Orphanage at Village Khanpur, District Ropar, Punjab" by "Nishkam Sikh Welfare Council, BF-33, Tagore Garden, New Delhi-110027", as an eligible project or scheme for a period of two years beginning with assessment year 1996-1997, which was extended further vide notification number S.O.259(E) dated the 27th March,1997, for a period of three year beginning with assessment year 1998-1999, which was extended further vide notification number S.O.924(E) dated the 20th September,2001, for a period of three year beginning with assessment year 2001-2002, which was extended further vide notification number S.O.724(E) dated the 23rd June, 2004 for a period of three year beginning with financial year 2003-2004, which was extended further vide notification number S.O. 480(E) dated the 29th March, 2007 for a period of three year beginning with financial year 2006-2007, which was extended further vide notification number S.O. 2054(E) dated 6th September, 2009 for a period of three year beginning with financial year 2009-10 and which was extended further vide notification number S.O. 666(E) dated 12th March, 2013 for a period of three year beginning with financial year 2012-13:

And whereas by notification number S.O.924(E) dated the 20th September, 2001 the estimated cost was enhanced from Rs.27.36 lakh to Rs.99.00 lakh and vide notification number S.O.724(E) dated the 23rd June, 2004 the estimated cost was enhanced from Rs.99.00 lakh to Rs.159.00 lakh;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond twenty one years;

And whereas the project cost is likely to enhance from Rs.159 lakh to Rs.350 lakh;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years and amending the project cost from Rs.159 lakh to Rs.350 lakh;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by subsection (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (a) hereby notifies the scheme or project "Running expenses for Mata Gujari Old Age Home-cum-Orphanage at Village Khanpur, District Ropar, Punjab", which is being carried out by "Nishkam Sikh Welfare Council, BF-33, Tagore Garden, New Delhi-110027", for a period of three years commencing with the financial year 2015-16 i.e. 2015-16, 2016-17 and 2017-18;

(b) further amends the said notification number S.O.844(E) dated the 17th October, 1995, to the following effect, namely:-

In the said notification, in the Table against serial number 14, in column (4), relating to maximum to be allowed as deduction under section 35AC of Income Tax Act, 1961, for the letters, figures and word "Rs. 159.00 lakh" the letters, figures and word "Rs. 350.00 lakh" shall be substituted.

[No. 186/2015/ F. No. V.27015/2/2015-SO (NAT.COM)] MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2015

का.आ. 1974(अ).—जबिक आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 19.12.2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 2835(अ.) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "विनय विहार एजुकेशन ट्रस्ट (लोक विद्यालय) वालुग्द तालुका-पालीतना, जिला भावनगर, राज्य गुजरात-364270" द्वारा "ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चलती फिरती चिकित्सा परियोजना, सामाजिक/आर्थिक रूप से निर्धन लड़िकयों के लिए छात्रावास एवं शिक्षा, बेरोजगारी महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए 2.50 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 6.44 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 5 पर अधिसूचित किया था;

और जबिक उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबिक सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अविध के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा "विनय विहार एजुकेशन ट्रस्ट (लोक विद्यालय) वालुग्द तालुका-पालीतना, जिला भावनगर, राज्य गुजरात-364270' द्वारा चलाई जा रही "ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चलती फिरती चिकित्सा परियोजना, सामाजिक/आर्थिक रूप से निर्धन लड़िकयों के लिए छात्रावास एवं शिक्षा, बेरोजगारी महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र" की परियोजना अथवा स्कीम को 2.50 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 6.44 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना, वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अविध अर्थात 2015-16, 2016-17 और 2017-2018 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 187/2015/फा. सं. वी-27015/2/2015-एस ओ (रा.स.)] मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

New Delhi, the 20th July, 2015

**S.O. 1974(E).**— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2835(E) dated 19.12.2011 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 5, "Medical mobile project for rural villages. Hostel accommodation and Education for socio economically poor girls. Vocational training centre for unemployed women" by "Vinay Vihar Education Trust, (Lok Vidyalaya), Valukd Taluka- Palitana), District Bhavnagar State, Gujarat –364270", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Cost of Rs. 6.44 crore including a corpus fund of Rs. 2.50 crore for a period of three years ending with financial year 2014-15;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Medical mobile project for rural villages. Hostel accommodation and Education for socio economically poor girls. Vocational training centre for unemployed women", which is being carried out by "Vinay Vihar Education Trust, (Lok Vidyalaya), Valukd Taluka- Palitana), District Bhavnagar State, Gujarat –364270", without any change in the approved cost of Cost of Rs. 6.44 crore including a corpus fund of Rs. 2.50 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2015-16 i.e 2015-16, 2016-17 & 2017-18.

[No. 187/2015/ F. No. V.27015/2/2015-SO(NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2015

का.आ. 1975(अ).—जबिक आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 12.03.2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 627(अ.) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "परिवार एजुकेशन सोसायटी, बोनोग्राम, बखराहट रोड, डाकखाना रासपुंज, कोलकाता-700104, पश्चिम बंगाल" द्वारा "परिवार एजुकेशन सोसायटी का अवसंरचनात्मक विकास" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए 12.15 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 9 पर अधिसूचित किया था;

और जबिक उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबिक सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अविध के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसिलए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा "परिवार एजुकेशन सोसायटी, बोनोग्राम, बखराहट रोड, डाकखाना रासपुंज, कोलकाता-700104, पश्चिम बंगाल" द्वारा चलाई जा रही "परिवार एजुकेशन सोसायटी का अवसंरचनात्मक विकास" की परियोजना अथवा स्कीम को 12.15 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना, वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अविध अर्थात 2015-16, 2016-17 और 2017-2018 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 188/2015/फा. सं. वी-27015/2/2015-एस ओ (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

New Delhi, the 20th July, 2015

**S.O. 1975(E).**—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 627(E) dated 12.03.2013 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 9, "Infrastructure Development of Parivar Education Society" by "Parivar Education Society, Bonogram, Bakhrahat Road, P.O. Raspunja, Kolkata – 700 104, West Bengal", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 12.15 crore for a period of three years ending with financial year 2014-15;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Infrastructure Development of Parivar Education Society", which is being carried out by "Parivar Education Society, Bonogram, Bakhrahat Road, P.O. Raspunja, Kolkata – 700 104, West Bengal", without any change in the approved cost of Rs. 12.15 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2015-16 i.e 2015-16, 2016-17 & 2017-18.

[No. 188/2015/ F. No. V.27015/2/2015-SO(NAT.COM)] MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2015

का.आ. 1976(अ).— जबिक आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 09.03.2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 406(अ.) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने 'वाणी, डीफ चिल्ड्रनस फाउंडेशन, 9 डी, अन्नपूर्णा अपार्टमेंट्स, 68 बालीगंज, सर्कल रोड, कोलकाता-700019'' द्वारा ''बहरे बच्चों, उनके परिवारों तथा व्यवसायिकों, जो बहरे बच्चों के साथ कार्य करते हैं, के लिए व्यापक सेवाएं' की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए एक पात्र परियोजना अथवा सकीम के रूप में क्रम सं. 9 पर अधिसूचित किया था;

और जबिक उकत परियोजना या सकीम के तीन वर्षों से अधिक तक चलने की संभावना है ;

और जबिक परियोजना लागत को 2.90 करोड़ रूपए से बढ़ाकर 3.35 करोड़ रूपए करने की संभावना है;

और जबिक सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 इ के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना या स्कीम को अगले तीन वर्षों की अविध के लिए विनिदिष्ट करने तथा परियोजना लागत को 2.90 करोड़ रुपए से संशोधित कर 3.35 करोड़ रुपए करने की सिफारिश की है:

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा (क) ''वाणी, डीफ चिल्ड्रनस फाउंडेशन, 9 डी, अन्नपूर्णा अपार्टमेंट्स, 68 बालीगंज, सर्कल रोड, कोलकाता-700019'' द्वारा चलाई जा रही ''बहरे बच्चों, उनके परिवारों तथा व्यवसायिकों, जो बहरे बच्चों के साथ कार्य करते हैं, के लिए व्यापक सेवाएं'' की स्कीम या परियोजना को वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि अर्थात 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए और बढ़ाने को अधिसूचित करती है और;

(ख) दिनांक 09.03.2012 की उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 406(अ) को निम्नलिखित आशय के लिए और संशोधित करती है, नामत:-

उक्त अधिसूचना में आयकर अधिनियम,1961की धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम राशि से संबंधित क्रम. सं. (9), कालम (4) के सामने सारणी में, ''2.90 करोड़ रुपए'' अक्षरों, अंकों और शब्दों के लिए ''3.35 करोड़ रुपए'' अक्षर, अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं. 189/2015/फा. सं. वी-27015/2/2015-एस ओ (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2015

**S.O. 1976(E).**— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 406(E) dated 09.03.2012 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 9, "Comprehensive Services for Deaf Children, their families and professionals who work with deaf children" by "VAANI, Deaf Children's Foundation, 9D, Annapurna Apartments, 68 Ballygunge Circular Road, Kolkata-700019", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 2.90 crores for a period of three years ending with financial year 2014-15;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the project cost is likely to enhance from Rs. 2.90 crore to Rs.3.35 crore;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years and amending the project cost from Rs. 2.90 crore to Rs.3.35 crore.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (a) hereby notifies the scheme or project "Comprehensive Services for Deaf Children, their families and professionals who work with deaf children", which is being carried out by "VAANI, Deaf Children's Foundation, 9D, Annapurna Apartments, 68 Ballygunge Circular Road, Kolkata-700019", for a further period of three years commencing with the financial year 2015-16 i.e. 2015-16, 2016-17 and 2017-18 and;

(b) further amends the said notification number S.O. 406(E) dated 09.03.2012, to the following effect, namely:-

In the said notification, in the Table against serial number 9, in column (4), relating to maximum to be allowed as deduction under section 35AC of Income Tax Act, 1961, for the letters, figures and word "Rs. 2.90 crore" the letters, figures and word "Rs. 3.35 crore" shall be substituted.

[No. 189/2015/ F. No. V.27015/2/2015-SO(NAT.COM)] MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2015

का.आ. 1977(अ).—जबिक आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 11.05.2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 1052(अ.) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "डॉ० बाबासाहेब अंबेडकर वेदकीय प्रतिष्ठान, गजानन महाराज मंदिर के सामने, गारखेड़ा परिसर, औरंगाबाद" द्वारा "जीवनज्योति-द हीलिंग टच एक्सपेंशन प्रोजेक्ट" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में 1880.66 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर क्रम सं. 10 पर अधिसूचित किया था, और जिसे बाद में दिनांक 12.03.2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 643(अ.) के तहत वित्तीय वर्ष 2015-2016 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबिक दिनांक 31 जुलाई, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ. 1939(अ.) द्वारा परियोजना लागत को 1880.66 लाख रुपए से 2000 लाख रुपए तक बढा दिया गया था:

और जबिक परियोजना लागत के 2000 लाख रुपए से 4000 लाख रुपए तक बढाने की संभावना है:

और जबिक सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम की परियोजना लागत को अनुमोदित अविध अर्थात वित्तीय वर्ष 2015-16 तक के लिए 2000 लाख रुपए से 4000 लाख रुपए तक संशोधित करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा दिनांक 11.05.2010 की उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 1052(अ) को निम्निलिखित आशय के लिए संशोधित करती है, नामत:-

'उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 10 के सामने तालिका में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत्य की जाने वाली अधिकतम राशि से संबंधित कालम (4) में "2000 लाख रुपए" अक्षरों, अंकों और शब्दों को "4000 लाख रुपए" अक्षरों, अंकों और शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[सं. 190/2015/फा. सं. वी-27015/2/2015-एस ओ (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th July, 2015

**S.O. 1977(E).**— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.1052(E) dated 11.5.2010 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 10, "Jeevanjyoti-The Healing Touch Expansion project" by "Dr. Babasaheb Ambedkar Vaidyakiya Pratisthan, Opposite Gajanan Maharaj Mandir, Garkheda Parisar, Aurangabad", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs.1880.66 lakh, for a period of three years ending with financial year 2012-13 and which was further extending vide notification number S.O. 643(E) dated 12.3.2013 for a further period of three years ending with financial year 2015-16;

And whereas by notification number S.O.1939(E) dated the 31st July, 2014 the estimated cost was enhanced from Rs.1880.66 lakh to Rs. 2000 lakh;

And whereas the project cost is likely to enhance from Rs.2000 lakh to Rs.4000 lakh;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for enhancing the project cost from Rs.2000 lakh to Rs.4000 lakh for the approved period i.e. upto financial years 2015-16;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby amends the said notification number S.O.1052(E) dated 11.5.2010, to the following effect, namely:-

'In the said notification, in the Table against serial number (10), in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC, for the letters, figures and words "Rs. 2000 lakh", the letters, figures and words "Rs. 4000 lakh" shall be substituted'.

[No. 190/2015/ F. No. V.27015/2/2015-SO (NAT.COM)] MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2015

का.आ. 1978(अ).—जबिक आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 3 अक्तूबर, 1997 की अधिसूचना सं. का.आ. 698(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "नवसारी लॉयन्स सार्वजनिक चेरिटेबल ट्रस्ट, आशापुरी रोड, दूधिया तालाव, नवसारी, गुजरात-396445" द्वारा "नवसारी, गुजरात में स्थित मणिलाल रिखावचंद कोठारी लॉयन्स ऑथोंपैडिक एवं जनरल हॉस्पिटल के लिए उपकरणों की खरीद और उक्त हॉस्पिटल को चलाने" की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1998-99 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 12 पर विनिर्दिष्ट किया था; जिसे बाद में दिनांक 29 मार्च, 2000 की अधिसूचना सं. का.आ. 304(अ) के तहत निर्धारण वर्ष 2001-2002 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 05 जुलाई, 2004 की अधिसूचना सं. का.आ. 791(अ) द्वारा वित्तीय

वर्ष 2003-04 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 16 जुलाई, 2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 1155(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 25 मार्च, 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 853(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए और बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 12 मार्च, 2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 659(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबिक दिनांक 16 जुलाई, 2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 1155(अ) द्वारा अनुमानित लागत को 156.80 लाख रू० से बढ़ाकर 2.00 करोड़ रूपये की काँपर्स निधि सहित 4.00 करोड़ रूपये कर दिया गया था;

और जबिक उक्त परियोजना या स्कीम के 18 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबिक सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अविध के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

इसिलए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पिठत उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा "नवसारी लॉयन्स सार्वजिनक चेरिटेबल ट्रस्ट, आशापुरी रोड, दूधिया तालाव, नवसारी, गुजरात-396445" द्वारा चलाई जा रही "नवसारी, गुजरात में स्थित मणिलाल रिखावचंद कोठारी लॉयन्स ऑथॉपैडिक एवं जनरल हॉस्पिटल के लिए उपकरणों की खरीद और उक्त हॉस्पिटल को चलाने" की परियोजना अथवा स्कीम को 2.00 करोड़ रूपये की कॉपर्स निधि सिहत 4.00 करोड़ रूपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अविध अर्थात 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिस्चित करती है।

[सं. 1**91**/2015/फा. सं. वी-27015/2/2015-एस ओ (रा.स.)] मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2015

S.O. 1978(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O.698(E) dated the 3rd October, 1997, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 12, "Purchase of equipments for Manilal Rikhavchand Kothari Lions Orthopedic and General Hospital and running of said hospital at Navsari, Gujarat", by "Navsari Lions Sarvajanik Charitable Trust, Ashapuri Road, Dudhia Talav, Navsari, Gujarat – 396445", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1998-1999, which was extended further vide notification number S.O.304(E) dated the 29th March, 2000 for a period of three years beginning with assessment year 2001-2002, which was extended further vide notification number S.O.791(E) dated the 5th July, 2004 for a period of three years beginning with financial year 2003-2004, which was extended further vide notification number S.O. 853(E) dated 25th March, 2009 for a period of three years beginning with financial year 2009-10 and which was extended further vide notification number S.O. 659(E) dated 12th March, 2013 for a period of three years ending with financial year 2014-15;

And whereas by notification number S.O.1155(E) dated the 16th July, 2007 the estimated cost was enhanced from Rs.156.80 lakh to Rs.4.00 crore including a corpus fund of Rs.2.00 crore;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond eighteen years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Purchase of equipments for Manilal Rikhavchand Kothari Lions Orthopedic and General Hospital and running of said hospital at Navsari, Gujarat" which is being carried out by "Navsari Lions Sarvajanik Charitable Trust, Ashapuri Road, Dudhia Talav, Navsari, Gujarat – 396445", without any change in the approved cost of Rs. 4.00 crore including a corpus fund of Rs. 2.00 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial year 2015-16 i.e. 2015-16, 2016-17 and 2017-18.

[No. 191/2015/ F. No. V.27015/2/2015-SO (NAT.COM)] MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2015

का.आ. 1979(अ).—जबिक आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 18.03.2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 614(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "अर्पित महिला एवं ग्रामीण विकास संस्थान, 242, भाभा नगर, सानीगवान रोड, कानपुर नगर-21 उत्तर प्रदेश" द्वारा "एचआईवी/एड्स जागरूकता, प्रशिक्षण एवं पुनर्वास कार्यक्रम" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अविध के लिए 1 करोड़ रूपये की कार्पस निधि सहित 5.92 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 19 पर अधिसूचित किया था;

और जबिक उक्त परियोजना या स्कीम के 3 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबिक सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अविध के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पिठत उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, "अर्पित मिहला एवं ग्रामीण विकास संस्थान, 242, भाभा नगर, सानीगवान रोड, कानपुर नगर-21 उत्तर प्रदेश" द्वारा चलाई जा रही "एचआईवी/एड्स जागरूकता, प्रशिक्षण एवं पुनर्वास कार्यक्रम" की परियोजना अथवा स्कीम को 1 करोड़ रूपये की कॉर्पस निधि सिहत 5.92 करोड़ रूपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अविध अर्थात 2013-14, 2014-15 और 2015-2016 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है। क्योंकि वित्तीय वर्ष 2013-14 और 2014-15 पहले ही समाप्त हो चुके हैं, इसलिए उक्त वित्तीय वर्षों 2013-14 और 2014-15 के लिए कोई छूट उपलब्ध नहीं होगी।

[सं. 192/2015/फा. सं. वी-27015/2/2015-एस ओ (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th July, 2015

**S.O. 1979(E).**— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 614(E) dated 18.03.2010 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 19, "HIV/AIDS awareness, training and rehabilitation programme" by "Arpit Mahila Evam Gramin Vikas Sansthan, 242, Bhabha Nagar, Sanigwan Raod, Kanpur Nagar –21, Uttar Pradesh", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs.5.92 crore including corpus fund of Rs.1 crore for a period of three years ending with financial year 2012-13;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "HIV/AIDS awareness, training and rehabilitation programme", which is being carried out by "Arpit Mahila Evam Gramin Vikas Sansthan, 242, Bhabha Nagar, Sanigwan Raod, Kanpur Nagar –21, Uttar Pradesh", without any change in the approved cost of Rs.5.92 crore including corpus fund of Rs.1 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2013-14 i.e. 2013-14, 2014-15 and 2015-16. Since the financial years 2013-2014 and 2014-15 are already lapsed, no exemption shall be available for the said financial years 2013-2014 and 2014-15.

[No. 192/2015/ F. No. V.27015/2/2015-SO(NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2015

का.आ. 1980(अ).—जबिक आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 04.10.2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 2366(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "मानव सेवा धर्म संवर्धनी, 391/1, वेंकटाचलापेथी नगर, अलापक्कम, चेन्नई-600116, तमिलनाडु" द्वारा "कॉर्पस निधि के रूप में 3.40 करोड़ रूपये की कॉपर्स निधि के स्प में गिरियोजना को वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए कार्पस निधि के रूप में 3.40 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 23 पर अधिसूचित किया था;

और जबिक उक्त परियोजना या स्कीम के 3 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबिक सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अविध के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, "मानव सेवा धर्म संवर्धनी, 391/1, वेंकटाचलापेथी नगर, अलापक्कम, चेन्नई-600116, तिमलनाडु" द्वारा चलाई जा रही "कॉर्पस निधि के रूप में 3.40 करोड़ रूपये की कॉपर्स निधि के सृजन" की परियोजना अथवा स्कीम को कॉर्पस निधि के रूप में 3.40 करोड़ रूपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अविध अर्थात 2015-16, 2016-17 और 2017-2018 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 193/2015/फा. सं. वी-27015/2/2015-एस ओ (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th July, 2015

**S.O. 1980(E).**— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2366(E) dated 4.10.2012 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 23, "Creation of a corpus fund of Rs. 3.40 crore as corpus fund" by "Manava Seva Dharma Samvardhani, 391/1, Venkatachalapathy Nagar, Alapakkam, Chennai – 600 116, Tamil Nadu", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 3.40 crore as corpus fund for a period of three years ending with financial year 2014-15;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Creation of a corpus fund of Rs. 3.40 crore as corpus fund", which is being carried out by "Manava Seva Dharma Samvardhani, 391/1, Venkatachalapathy Nagar, Alapakkam, Chennai – 600 116, Tamil Nadu", without any change in the approved cost of Rs.3.40 crore as corpus fund, for a further period of three years commencing with financial year financial year 2015-16 i.e. 2015-16, 2016-17 and 2017-18.

[No. 193/2015/ F. No. V.27015/2/2015-SO (NAT.COM)] MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2015

का.आ. 1981(अ).—जबिक आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पिठत उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 6 अगस्त, 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 2033(अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने "सेवालय, सेवालय कैम्पस, कसुवा गांव, पक्कम पोस्ट, नजदीक थिरूनिनरावुर-602024" द्वारा "सेवालय वृद्धाश्रम परियोजना" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2009-2010 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 9 पर अधिसूचित किया था और जिसे बाद में दिनांक 27 दिसम्बर, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 2897(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबिक उक्त परियोजना अथवा स्कीम को छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबिक सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे तीन वर्षों की अविध के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है।

इसलिए, अब, केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, "सेवालय, सेवालय कैम्पस, कसुवा गांव, पक्क्म पोस्ट, नजदीक थिरूनिनरावुर-602024" द्वारा चलाई जा रही "सेवालय वृद्धाश्रम परियोजना" परियोजना को 95 लाख रूपये की कार्पस निधि तथा 19.86 लाख रूपये के आवर्ती व्यय सहित 1.15 करोड़ रूपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अविध अर्थात् 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 194/2015/फा. सं. वी-27015/2/2015-एस ओ (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th July, 2015

**S.O. 1981(E).**— Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2033(E) dated 6th August, 2009, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 9, "Sevalaya old age home project" by "Sevalaya, Sevalaya Campus, Kasuva Village, Pakkam Post, Near Thiruninravur-602024", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2009-10 and which was extended further vide notification number S.O. 2897(E) dated 27th December, 2011 for a period of three years ending with financial year 2014-15;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Sevalaya old age home project" which is being carried out by "Sevalaya, Sevalaya Campus, Kasuva Village, Pakkam Post, Near Thiruninravur-602024", without any change in the approved cost of Rs. 1.15 crore including a corpus of Rs. 95 lakh and Rs. 19.86 lakh recurring expenditure, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with the financial year 2015-16 i.e. 2015-16, 2016-17 and 2017-18.

[No. 194/2015/ F. No. V-27015/2/2015-SO (NAT.COM)] MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2015

का.आ. 1982(अ).—जबिक आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 18 सितम्बर, 1998 की अधिसूचना सं. का.आ. 832(अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने "ईएनटी चैरीटेबल ट्रस्ट, 4, फिल्का, दफ्तरी रोड, मुम्बई-400097" द्वारा "बंदानगढ़ी, मलाड पूर्व, मुम्बई में कानों की देखभाल हेतु स्कूल तथा सेन्टर के लिए उपकरणों की खरीद तथा बिल्डिंग का निर्माण" की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 2 पर विर्निदिष्ट किया था, जिसे बाद में दिनांक 20 जून, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 564(अ) द्वारा निर्धारण वर्ष 2002-03 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था, जिसे बाद में दिनांक 3 फरवरी, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 142(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-06 से प्रारंभ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था, जिसे दिनांक 14 अक्टूबर, 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 2614(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था, जिसे दिनांक 14 अक्टूबर, 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 2614(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 9 अक्टूबर, 2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 2413(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबिक दिनांक 17 अक्टूबर, 2013 की अधिसूचना सं. का0 आ0 3140(अ) द्वारा अनुमानित लागत को 3.75 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 8.75 करोड़ रू. कर दिया गया था।

और जबिक उक्त परियोजना अथवा स्कीम को सोलह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबिक सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे तीन वर्षों की अविध के लिए विर्निदिष्ट करने की सिफारिश की है।

इसलिए, अब, केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा, "ईएनटी चैरीटेबल ट्रस्ट, 4, फिल्का, दफ्तरी रोड, मुम्बई-400097" द्वारा चलाई जा रही "बंदानगढ़ी, मलाड पूर्व, मुम्बई में कानों की देखभाल हेतु स्कूल तथा सेन्टर के लिए उपकरणों की खरीद तथा बिल्डिंग का निर्माण" परियोजना को 8.75 करोड़ रूपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अविध अर्थात् 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 1**95**/2015/फा. सं. वी-27015/2/2015-एस ओ (रा.स.)] मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्टीय समिति)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th July, 2015

**S.O. 1982(E).**— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O.832(E) dated the 18th September, 1998, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 2, "Purchase of equipments, construction of building for school and centre for the care of ear at Bandangari, Malad East, Mumbai" by "ENT Charitable Trust, 4, Filka, Daftry Road, Mumbai – 400097", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1999-2000, which was extended further vide notification number S.O.564(E) dated the 20th June, 2001 for a period of three years beginning with assessment year 2002-2003, which was extended further vide notification number S.O.142(E) dated the 3rd February, 2006 for a period of one year beginning with financial year 2005-2006, which was extended further vide notification number S.O.1153(E) dated the 16th July, 2007 for a period of three years beginning with financial year 2006-2007, which was extended further vide notification number S.O. 2614(E) dated 14th October, 2009 for a period of three years beginning with financial year 2009-10 and which was extended further vide notification number S.O. 2413(E) dated 9th October, 2012 for a period of three years ending with financial year 2014-15;

And whereas by notification number S.O.3140(E) dated the 17th October, 2013 the estimated cost was enhanced from Rs. 3.75 crore to Rs. 8.75 crore;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond sixteen years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Purchase of equipments, construction of building for school and centre for the care of ear at Bandangari, Malad East, Mumbai" which is being carried out by "ENT Charitable Trust, 4, Filka, Daftry Road, Mumbai – 400097", without any change in the approved cost of Rs. 8.75 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial year 2015-16 i.e. 2015-16, 2016-17 and 2017-18.

[No. 195/2015/ F. No. V-27015/2/2015-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2015

का.आ. 1983(अ).—जबिक आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 6 अक्टूबर, 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 2545(अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने "आर ई ए डी एस—ग्रामीण शिक्षा तथा विकास सोसायटी, 31/34, अलाहगिरी सेंट, चेटपेट (पोलुर), तिरुवन्नामलाई जिला, पिन-606801" द्वारा "वाटर शेड प्रोजेक्ट" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2011-2012 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए 69.50 लाख रूपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 11 पर अधिसूचित किया था और जिसे बाद में दिनांक 31 जुलाई, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ. 1927(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबिक उक्त परियोजना अथवा स्कीम को छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबिक सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे तीन वर्षों की अविध के लिए विर्निदिष्ट करने की सिफारिश की है।

इसलिए, अब, केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा, "आर ई ए डी एस—ग्रामीण शिक्षा तथा विकास सोसायटी, 31/34, अलाहगिरी सेंट, चेटपेट (पोलुर), तिरूवन्नामलाई जिला, पिन-606801" द्वारा चलाई जा रही "वाटर शेड प्रोजेक्ट" परियोजना को 69.50 लाख रूपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अविध अर्थात् 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 196/2015/फा. सं. वी-27015/2/2015-एस ओ (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th July, 2015

**S.O. 1983(E).**— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2545(E) dated 6.10.2009 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 11, "Watershed Project" by "READS – Rural Education and Development Society, 31/34, Alagiri St., Chetpet (Polur), Tiruvannamalai District, Pin – 606801", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs.69.50 lakh for a period of three years ending with financial year 2011-12 and which was extended further vide notification number S.O. 1927(E) dated 31st July, 2014 for a period of three years ending with financial year 2014-15;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Watershed Project", which is being carried out by "READS – Rural Education and Development Society, 31/34, Alagiri St., Chetpet (Polur), Tiruvannamalai District, Pin – 606801", without any change in the approved cost of Rs.69.50 lakh, for a further period of three years commencing with financial year 2015-16 i.e. 2015-16, 2016-17 and 2017-18.

[No. 196/2015/ F. No. V.27015/2/2015-SO (NAT.COM)] MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2015

का.आ. 1984(अ).—जबिक आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 30 मार्च, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 458(अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने "सेवासंघ सार्वजनिक हास्पिटल ट्रस्ट, मोदासा-383315, जिला साबरकांथा, गुजरात" द्वारा "हास्पिटल प्रोजेक्ट" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 16 पर अधिसूचित किया था, जिसे बाद में दिनांक 6 अगस्त, 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 2037(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 16 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 474(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबिक दिनांक 30 दिसम्बर 2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 3065(अ) द्वारा 50.00 लाख रूपये की कार्पस निधि सिहत एक करोड़ रूपये की अनुमानित लागत को बढ़ाकर एक करोड़ रूपये की कार्पस निधि सिहत 2 करोड़ रूपये कर दिया गया था:

और जबिक उक्त परियोजना अथवा स्कीम को नौ वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबिक सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे तीन वर्षों की अविध के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है।

इसलिए, अब, केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा, "सेवा संघ सार्वजनिक हास्पिटल ट्रस्ट, मोदासा-383315,जिला साबरकांथा, गुजरात" द्वारा चलाई जा रही "हास्पिटल प्रोजेक्ट" परियोजना को एक करोड़ रूपये की कार्पस निधि सिहत 2 करोड़ रूपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अविध अर्थात् 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 197/2015/फा. सं. वी-27015/2/2015-एस ओ (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2015

**S.O. 1984(E).**— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.458(E) dated the 30th March, 2006, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 16, "Hospital project" by "Sevasangh, Sarvajanik Hospital Trust, Modasa – 383315, District Sabarkantha, Gujarat", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2006-2007, which was extended further vide notification number S.O. 2037(E) dated the 6th August, 2009 for a period of three years beginning with financial year 2009-10 and which was extended further vide notification number S.O. 474(E) dated the 16th March, 2012 for a period of three years beginning with financial year 2012-13;

And whereas by notification number S.O.3065(E) dated the 30th December, 2010 the estimated cost was enhanced from Rs. 1 crore including corpus fund of 50.00 lakh to Rs. 2 crore including corpus fund of Rs. 1 crore.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond nine years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Hospital project" which is being carried out by "Sevasangh Sarvajanik Hospital Trust, Modasa – 383315, District Sabarkantha, Gujarat", without any change in the approved cost of Rs. 2 crore including corpus fund of Rs. 1 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with the financial year 2015-16 i.e. 2015-16, 2016-17 and 2017-18.

[No. 197/2015/ F. No. V.27015/2/2015-SO (NAT.COM)] MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2015

का.आ. 1985(अ).—जबिक आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 18.03.2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 614(अ.) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "एमपथी फाउन्डेशन, 405 कुशाल कमर्शियल काम्प्लेक्स, शॉपर स्टाप के ऊपर, जी. एम. रोड, चेम्बूर (पश्चिम), मुंबई-40089, महाराष्ट्र" द्वारा "चिकित्सा कैम्प" की परियोजना या स्कीम को वित्तीय वर्ष 2009-10 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 1 पर अधिसूचित किया था और जिसे बाद में दिनांक 16.03.2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 484(अ.) के तहत वित्तीय वर्ष 2012-2013 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबिक उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबिक परियोजना लागत को 2.97 करोड़ रुपए से 7.60 करोड़ रुपए तक बढ़ाए जाने की संभावना है ;

और जबिक सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय सिमिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस सिमिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अविध के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है:

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा "एमपथी फाउन्डेशन, 405 कुशाल कमर्शियल काम्प्लेक्स, शॉपर स्टाप के ऊपर, जी. एम. रोड, चेम्बूर (पश्चिम), मुंबई-40089, , महाराष्ट्र"" द्वारा चलाई जा रही "चिकित्सा कैम्प" की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अविध अर्थात 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है; और

(ख) दिनांक 18.03.2010 की उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 614(अ.) को निम्नलिखित आशय के लिए और आगे संशोधित करती है, नामत :-

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 1 के सामने तालिका में, आयकर अधिनियम की धारा 1961की धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम राशि से संबंधित कालम (4) में '2.97 करोड़ रुपए' अक्षरों, अंकों और शब्दों के लिए '7.60 करोड़ रुपए' अक्षर, अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं. 198/2015/फा. सं. वी-27015/2/2015-एस ओ (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th July, 2015

**S.O. 1985(E).**— Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 614(E) dated 18th March, 2010, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 1, "Medical Camps" by "Empathy Foundation, 405, Krushal Commercial Complex, Above Shopper's Stop, G.M.Road, Chembur (West), Mumbai – 400 089, Maharashtra", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2009-10 and which was extended further vide notification number S.O. 484(E) dated the 16th March, 2012 for a period of three years beginning with financial year 2012-13;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the project cost is likely to enhance from Rs. 2.97 crores to Rs.7.60 crores;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), -(a) hereby notifies the scheme or project "Medical Camps" which is being carried out by "Empathy Foundation, 405, Krushal Commercial Complex, Above Shopper's Stop, G.M.Road, Chembur (West), Mumbai – 400 089, Maharashtra", as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with the financial year 2015-16 i.e. 2015-16, 2016-17 and 2017-18 and;

(b) further amends the said notification number S.O. 614(E) dated 18th March, 2010, to the following effect, namely:-

In the said notification, in the Table against serial number 1, in column (4), relating to maximum to be allowed as deduction under section 35AC of Income Tax Act, 1961, for the letters, figures and word "Rs. 2.97 crore" the letters, figures and word "Rs. 7.60 crores" shall be substituted.

[No. 198/2015/ F. No.-V.27015/2/2015-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2015

का.आ. 1986(अ).—जबिक आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 11.11.2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1586(अ.) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने 'वात्सल्य ट्रस्ट, सी-2/32, श्री विजय कुंज सोसायटी, कंजूर मार्ग (पूर्व), मुंबई-400042" द्वारा "i) अनाथालय, ii) बालिका आश्रम, iii) वृद्धावस्था गृह, iv) बाल माता-पिता मार्ग दर्शन केंद्रों" की परियोजना या स्कीम को वित्तीय वर्ष 2007-08 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 9 पर अधिसूचित किया था और जिसे बाद में दिनांक 03.10.2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 2391(अ.) के तहत वित्तीय वर्ष 2010-2011 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 18.10.2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 2399(अ.) के तहत वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए और बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 31.07.2014 की अधिसूचना सं. का.आ. 1971(अ.) के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए और बढ़ा दिया गया था और जिसे वर्षों की अविध के लिए और बढ़ा दिया गया था।

और जबिक परियोजना लागत को 1.92 करोड़ रुपए से 5.00 करोड़ रुपए तक बढ़ाए जाने की संभावना है ;

और जबिक सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अनुमोदित अविध अर्थात वित्तीय वर्ष 2016-17 तक बढ़ाने और परियोजना लागत को 1.92 करोड़ रुपए से 5.00 करोड़ रुपए तक संशोधित करने की सिफारिश की है:

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा दिनांक 11.11.2005 की उक्त अधिसूचना सं. सां.आ. 1586(अ.) को निम्नलिखित आशय के लिए और आगे संशोधित करती है, नामत :-

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 9 के सामने तालिका में, आयकर अधिनियम की धारा 1961की धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम राशि से संबंधित कालम (4) में '1.92 करोड़ रुपए' अक्षरों, अंकों और शब्दों के लिए '5.00 करोड़ रुपए' अक्षर, अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।'

[सं. 199/2015/फा. सं. वी-27015/2/2015-एस ओ (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th July, 2015

**S.O. 1986(E).**— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1586(E) dated 11.11.2005 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 9, "i)Orphanage, ii) Balika Ashrama ,(iii) Old age home, (iv) Child parents guidance centers", by "Vatsalya Trust, C-2/32, Shree Vijay Kunj Society, Kanjur Marg (East), Mumbai 400042", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs.1.92 crore, for a period of three years ending with financial year 2007-08, which was further extended vide notification number S.O. 2391(E) dated 3.10.2008 for a period of three years ending with financial year 2010-11, which was further extended vide notification number S.O. 2399(E) dated 18.10.2011 for a period of three years ending with financial year 2013-14 and which was further extended vide notification number S.O. 1971(E) dated 31.07.2014 for a period of three years ending with financial year 2016-17;

And whereas the project cost is likely to enhance from Rs. 1.92 crore to Rs. 5.00 crore;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for amending the project cost from Rs. 1.92 crore to Rs. 5.00 crore for the approved period i.e. upto financial years 2016-17;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby amends the said notification number S.O. 1586(E) dated 11.11.2005, to the following effect, namely:-

In the said notification, in the Table against serial number 9, in column (4), relating to maximum to be allowed as deduction under section 35AC of Income Tax Act, 1961, for the letters, figures and word "Rs. 1.92 crore" the letters, figures and word "Rs. 5.00 crore" shall be substituted.

[No. 199/2015/ F. No. V.27015/2/2015-SO (NAT.COM)] MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2015

का.आ. 1987(अ).—जबिक आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 12.03.2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 627(अ.) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "महिला सेवा समिति, 5/1, रेड क्रास प्लेस, कोलकाता-700062" द्वारा "महिला सेवा समिति" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए कार्पस निधि के रूप में 3.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 18 पर अधिसूचित किया था;

और जबिक उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबिक सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अविध के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा "मिहला सेवा सिमिति, 5/1, रेड क्रास प्लेस, कोलकाता-700062" द्वारा चलाई जा रही "मिहला सेवा सिमिति" की परियोजना अथवा स्कीम को कार्पस निधि के रूप में 3.00 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना, वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अविध अर्थात 2015-16, 2016-17 और 2017-2018 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 200/2015/फा. सं. वी-27015/2/2015-एस ओ (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th July, 2015

**S.O. 1987(E).**— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 627(E) dated 12.03.2013 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 18, "Mahila Seva Samity" by "Mahila Seva Samity, 5/1, Red Cross Place, Kolkata – 700 062, West Bengal", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 3.00 crore as corpus fund for a period of three years ending with financial year 2014-15;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Mahila Seva Samity", which is being carried out by "Mahila Seva Samity, 5/1, Red Cross Place,

Kolkata- 700062, West Bengal", without any change in the approved cost of Rs. 3.00 crore as corpus fund, for a further period of three years commencing with financial year 2015-16 i.e 2015-16, 2016-17 & 2017-18.

[No. 200/2015/ F. No. V.27015/2/2015-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2015

का.आ. 1988(अ).—जबिक आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा(1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 29.03.1994 की अधिसूचना सं. का.आ. 267(अ.) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "अलर्ट-इंडिया (एसोसिएशन फार लेपरोसी एज्केशन, रिहेबलिटेशन और ट्रीटमेंट-इंडिया, 6वीं मुख्याध्यपक भवन, तीसरा तल, रोड सं. 24, सिओन (पश्चिम), बंबई-400022" द्वारा "(क) ग्रेटर बंबई और न्यू बंबई में शहरीकृष्ठ रोग नियंत्रण परियोजना; (ख) न्यू बंबई में तपेदिक नियंत्रण परियोजना के तहत तपेदिक रोगी-का पता लगाने, उपचार और रोगमुक्ति के लिए ; और (ग) एइरोली, बंबई में एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल परियोजना" की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1995-96 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 17 पर अधिसूचित किया था, और जिसे बाद में दिनांक 17.03.1997 की अधिसूचना सं. का.आ. 217(अ.) के तहत निर्धारण वर्ष 1998-1999 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया ; जिसे बाद में दिनांक 29.03.2000 की अधिसूचना सं. का.आ. 305(अ.) द्वारा वित्तीय वर्ष 2001-02 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ; जिसे बाद में दिनांक 13.06.2004 की अधिसूचना सं. का.आ. 683(अ.) द्वारा निर्धारण वर्ष 2004-05 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए और बढ़ा दिया गया था ; और जिसे बाद में दिनांक 26.10.2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1829(अ.) के तहत वित्तीय वर्ष 2006-07 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ; जिसे बाद में दिनांक 22.03.2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 636(अ.) के तहत वित्तीय वर्ष 2009-10 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 12.03.2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 645(अ.) के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था।

और जबिक दिनांक 06.01.1995 की अधिसूचना सं. का.आ. 21(अ.) के द्वारा अनुमानित लागत को 190.32 लाख रुपए से बढ़ाकर 12.52 लाख रुपए की कार्पस निधि सिहत 270.02 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया था और जबिक दिनांक 12.03.2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 645(अ.) द्वारा अनुमानित लागत को 12.52 लाख रुपए की कार्पस निधि सिहत 270.02 लाख रुपए से बढ़ाकर 65 लाख रुपए की कार्पस निधि सिहत 17.34 करोड़ रुपए कर दिया गया था;

और जबिक उक्त परियोजना या स्कीम के 21 वर्षों से अधिक तक चलने की संभावना है ;

और जबिक सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्ष की अविध के लिए बढाने की सिफारिश की है:

इसिलए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, "अलर्ट-इंडिया (एसोसिएशन फार लेपरोसी एजुकेशन, रिहेबिलिटेशन और ट्रीटमेंट-इंडिया, 6वीं मुख्याध्यपक भवन, तीसरा तल, रोड सं. 24, सिओन (पिश्चम), बंबई-400022" द्वारा चलाई जा रही "(क) ग्रेटर बंबई और न्यू बंबई में शहरीकुष्ठ रोग नियंत्रण परियोजना; (ख) न्यू बंबई में तपेदिक नियंत्रण परियोजना के तहत तपेदिक रोगी-का पता लगाने, उपचार और रोगम्कित के लिए

; और (ग) एड्रोली, बंबई में एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल परियोजना" की परियोजना अथवा स्कीम को 65 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 17.34 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाली वर्ष से आगे तीन वर्षों की अविध अर्थात 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए और एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. **20**1/2015/फा. सं. वी-27015/2/2015**-**एस ओ (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th July, 2015

S.O. 1988(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O.267(E) dated the 29th March, 1994, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 17, "for Detection, treatment and cure of- (a) leprosy patients under urban Leprosy Control Projects at Greater Bombay and New Bombay; (b) T.B. patients under T.B. Control Project at New Bombay; and (c) Running of Integrated health care project at Airoli, Bombay", by "ALERT-INDIA (Association for Leprosy Education, Rehabilitation and Treatment-India), 6B, Mukhyadhyapak Bhavan, 3rd Floor, Road No.24, Sion (W), Bombay-400022", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1995-1996, which was extended further vide notification number S.O.217(E) dated the 17th March,1997 for a period of three years beginning with assessment year 1998-1999, which was extended further vide notification number S.O.305(E) dated the 29th March, 2000 for a period of three years beginning with assessment year 2001-2002, which was extended further vide notification number S.O.683(E) dated the 13th June, 2003 for a period of three years beginning with assessment year 2004-2005, which was further extended vide notification number S.O. 1829(E) dated 26.10.2006 for a period of three years beginning with financial year 2006-07, which was extended further vide notification number S.O. 636(E) dated 22nd March, 2010 for a period of three years beginning with financial year 2009-10 and which was extended further vide notification number S.O. 645(E) dated 12th March, 2013 for a period of three years ending with financial year 2014-15;

And whereas by notification number S.O.21(E) dated the 6th January, 1995 the estimated cost was enhanced from Rs.190.32 lakh to Rs.270.02 lakh including a corpus funds of Rs. 12.52 lakh and whereas by notification number S.O. 645(E) dated 12th March, 2013 the estimated cost was enhanced from Rs.270.02 lakh including a corpus funds of Rs. 12.52 lakh to Rs. 17.34 crore including a corpus fund of Rs. 65 lakh;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond twenty one years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by subsection (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "for Detection, treatment and cure of- (a) leprosy patients under urban Leprosy Control Projects at Greater Bombay and New Bombay; (b) T.B. patients under T.B. Control Project at New Bombay; and (c) Running of Integrated health care project at Airoli, Bombay", which is being carried out by "ALERT-INDIA (Association for Leprosy Education, Rehabilitation and Treatment-India), 6B, Mukhyadhyapak Bhavan, 3rd Floor, Road No.24, Sion (W), Bombay-400022 ", as an eligible project or scheme without any change in the approved cost of Rs. 17.34 crore including a corpus fund of Rs. 65 lakh for a further period of three years commencing from the financial year 2015-16 i.e. 2015-16, 2016-17 & 2017-18.

[No. 201/2015/ F. No. V.27015/2/2015-SO (NAT.COM)] MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2015

का.आ. 1989(अ).—जबिक आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 17.03.1994 की अधिसूचना सं. का.आ. 228(अ.) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने " सेवा-ग्रामीण (सोसायटी फार एजुकेशन, वेलफेयर और कार्रवाई-ग्रामीण), डाकखाना झगाडिया, जिला बरुच-393110" द्वारा "ग्रामीण निर्धनों और जनजातियों के लिए स्वास्थ्य

और चिकित्सा सेवाओं के माध्यम से एकीकृत विकास, गरीबी उन्मूलन के लिए 15 से 35 वर्ष की आयु के बीच जनजातियों और ग्रामीण निर्धनों को व्यावसायिक प्रशिक्षण, महिलाओं के विकास के लिए आय पैदा करने वाला गतिविधियां, गरीबी उन्मूलन के लिए ग्रामोद्योग (कुटीर उद्योगों) का संवर्धन और निम्न लागत के मकानों को बनाने के लिए ग्रामीण निर्धनों को सहायता" की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1994-95 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 6 पर अधिसूचित किया था और जिसे बाद में दिनांक 06.06.1996 की अधिसूचना सं. का.आ. 403(अ.) के तहत निर्धारण वर्ष 1997-1998 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया ; जिसे बाद में दिनांक 10.09.1999 की अधिसूचना सं. का.आ. 748(अ.) द्वारा निर्धारण वर्ष 2001-02 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ; जिसे बाद में दिनांक 10.09.2002 की अधिसूचना सं. का.आ. 986(अ.) द्वारा निर्धारण वर्ष 2003-04 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए और बढ़ा दिया गया था ; जिसे बाद में दिनांक 04.04.2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 508(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-06 प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 04.06.2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 1297(अ.) के तहत वित्तीय वर्ष 2008-09 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए और बढ़ा दिया गया था ; जिसे बाद में दिनांक 14.06.2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 1383(अ.) के तहत वित्तीय वर्ष 2013-14 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 11.02.2015 की अधिसूचना सं. का.आ. 437(अ.) के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था।

और जबिक दिनांक 10.09.2002 की अधिसूचना सं. का.आ. 986(अ.) के द्वारा अनुमानित लागत को 418.50 लाख रुपए से बढ़ाकर 100.00 लाख रुपए की कार्पस निधि सिहत 518.50 लाख रुपए कर दिया गया था और जिसे दिनांक 14.06.2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 1383(अ.) द्वारा परियोजन लागत को 100 लाख रुपए की कार्पस निधि सिहत 518.50 लाख रुपए से बढ़ाकर 205 लाख रुपए की कार्पस निधि सिहत 918.45 लाख रुपए कर दिया गया था और जबिक दिनांक 11.02.2015 की अधिसूचना सं. का.आ. 437(अ.) के द्वारा परियोजना लागत को 205 लाख रुपए की कार्पस निधि सिहत 918.45 लाख रुपए से बढ़ाकर 205 लाख रुपए की कार्पस निधि सिहत 2297 लाख रुपए कर दिया गया था।

और जबिक परियोजना लागत को 205 लाख रुपए की कार्पस निधि सिहत 2297 लाख रुपए से 498 लाख रुपए की कार्पस निधि सिहत 2297 लाख रुपए तक बढ़ाए जाने की संभावना है ।

और जबिक सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम की परियोजना लागत को अनुमोदित अविध अर्थात वित्तीय वर्ष 2016-17 तक 205 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 2297 लाख रुपए से 498 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 2297 लाख रुपए तक संशोधित करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा दिनांक 17.03.1994 की उक्त अधिसूचना सं. सां.आ. 228(अ.) को निम्नलिखित आशय के लिए संशोधित करती है, नामत :-

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 6 के सामने तालिका में, आयकर अधिनियम की धारा 1961की धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम राशि से संबंधित कालम (4) में " 205 लाख रुपए की कार्पस निधि सिहत 2297 लाख रुपए" अक्षरों, अंकों और शब्दों के लिए " 205 लाख रुपए की कार्पस निधि सिहत 2297 लाख रुपए" अक्षर, अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगा ।'

[सं. **202**/2015/फा. सं. वी-27015/2/2015-एस ओ (रा.स.)] मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th July, 2015

S.O. 1989(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 228(E) dated the 17th March, 1994, issued under clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 6, "Integrated Rural Development through health and medical services for rural poor and tribals, vocational training to tribals and rural poor between age 15 to 35 years for poverty alleviation, income generation activities for development of woman, promotion of gramodyog (cottage industries) for poverty alleviation and help to rural poor for constructing low cost houses" by "SEWA-Rural (Society for Education, Welfare and Action-Rural), At & Post Office Jhagadia, District Bharuch-393110", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1994-1995; which was extended further vide notification number S.O. 403(E) dated the 6th June, 1996 for a period of three years beginning with assessment year 1997-1998; which was extended further vide notification number S.O.748(E) dated the 10th September, 1999 for a period of three years beginning with assessment year 2000-2001; which was extended further vide notification number S.O.986(E) dated the 10th September, 2002 for a period of three years beginning with assessment year 2003-2004; which was extended further vide notification number S.O.508(E) dated 4th April, 2006 for period of three years beginning with financial year 2005-2006; which was extended further vide notification number S.O. 1297(E) dated 4th June, 2008 for a period of three years beginning with financial year 2008-09 and which was further extended vide notification number S.O.1383(E) dated 14.6.2011 for a period of three years ending with financial year 2013-14 and which was further extended vide notification number S.O.437(E) dated 11.02.2015 for a period of three years ending with financial year 2016-17;

And whereas by notification number S.O.986(E) dated the 10th September, 2002 the estimated cost was enhanced from Rs. 418.50 lakh to Rs.518.50 lakh including a corpus find of Rs.100.00 lakh and whereas by notification number S.O.1383(E) dated 14.6.2011 the project cost was enhanced from 'Rs.518.50 lakh including corpus fund of Rs.100 lakh' to 'Rs.918., 45 lakh including corpus fund of Rs. 205 lakh' and the project cost was further enhanced from 'Rs.918.,45 lakh including corpus fund of Rs.205 lakh to Rs. 2297 lakh including corpus fund of Rs. 205 lakh vide notification number S.O. 437(E) dated 11.02.2015;

And whereas the project cost of Rs. 2297 lakh including corpus fund of Rs. 205 lakh is likely to be amended as Rs.2297 lakh including corpus fund of Rs.498 lakh;

And, whereas, the National Committee for the Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for amending the project cost from Rs. 2297 lakh including corpus fund of Rs.205 lakh to Rs.2297 lakh including corpus fund of Rs.498 lakh for the approved period i.e. upto financial years 2016-17;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby amends the said notification number S.O.228(E) dated the 17th March, 1994, to the following effect, namely:-

In the said notification, in the Table against serial number 6, in column (4), relating to maximum cost to be allowed as deduction under Section 35AC, for the letters, figures and word "Rs. 2297 lakh including a corpus fund of Rs. 205 lakh" the letters, figures and word "Rs. 2297 lakh including corpus fund of Rs. 498 lakh" shall be substituted.

 $[No.\ 202\ /2015/\ F.\ No.\ V.\ 27015/2/2015\text{-SO}\ (NAT.\ COM)]$ 

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2015

का.आ. 1990(अ).—जबिक आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 12.03.2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 627(अ.) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "दीपक फाउन्डेशन, दीपक फार्म, हरिकरुपा सोसायटी के सामने, टी बी अस्पताल के निकट, गोत्री रोड, वडोदरा-390021" द्वारा "वडोदरा, जिला गुजरात में लोक स्वास्थ्य प्रशिक्षण संस्थान" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए कार्पस निधि के रूप में 10 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 22 पर अधिसूचित किया था;

और जबिक उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबिक सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अविध के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है:

इसिलए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा "दीपक फाउन्डेशन, दीपक फार्म हरिकरुपा सोसायटी के सामने, टी बी अस्पताल के निकट, गोत्री रोड, वडोदरा-390021" द्वारा चलाई जा रही "वडोदरा जिला गुजरात में लोक स्वास्थ्य प्रशिक्षण संस्थान"की परियोजना अथवा स्कीम को कार्पस निधि के रूप में 10.00 करोड़ रूपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना, वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अविध अर्थात 2015-16, 2016-17 और 2017-2018 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 203/2015/फा. सं. वी-27015/2/2015-एस ओ (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th July, 2015

**S.O. 1990(E).**— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 627(E) dated 12.03.2013 issued under clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 22, "Public Health Training Institute, Vadodara District at Gujarat" by "Deepak Foundation, Deepak Farm, Opp. Harikrupa Society, Near TB Hospital Gotri Road, Vadodara-390021", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 10 crore as corpus fund for a period of three years ending with financial year 2014-15;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Public Health Training Institute, Vadodara District at Gujarat", which is being carried out by "Deepak Foundation, Deepak Farm, Opp. Harikrupa Society, Near TB Hospital Gotri Road, Vadodara-390021", without any change in the approved cost of Rs. 10.00 crore as corpus fund, for a further period of three years commencing with financial year 2015-16 i.e 2015-16, 2016-17 & 2017-18.

[No. 203/2015/ F. No. V.27015/2/2015-SO (NAT. COM)] MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2015

का.आ. 1991(अ).—जबिक आयंकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 17.11.2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 2907(अ.) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "इस्कान फूड रिलीफ फाउन्डेशन, हरे कृष्णा लैंड, जुहू, मुंबई-400049" द्वारा "राजस्थान राज्य में मध्यान्ह भोजन परियोजना" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2009-10 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 14 पर अधिसूचित किया था ; जिसे बाद में दिनांक 09.10.2012 की अधिसूचना सं.सां.आ. 2412(अ.) के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ;

और जबिक उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबिक सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अविध के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा "इस्कान फूड रिलीफ फाउन्डेशन, हरे कृष्णा लैंड, जुहू, मुंबई-400049" द्वारा चलाई जा रही "राजस्थान राज्य में मध्यान्ह भोजन परियोजना" की परियोजना अथवा स्कीम को 10.55 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना, वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2015-16, 2016-17 और 2017-2018 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 204/2015/फा. सं. वी-27015/2/2015-एस ओ (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th July, 2015

**S.O. 1991(E).**— Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2907 (E) dated 17th November, 2009, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 14, "Mid Day Meal Project in the state of Rajasthan" by "Iskcon Food Relief Foundation, Hare Krishna Land, Juhu , Mumbai –400049", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2009-10 and which was extended further vide notification number S.O. 2412(E) dated 9th October, 2012 for a period of three years ending with financial year 2014-15;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Mid Day Meal Project in the state of Rajasthan" which is being carried out by "Iskcon Food Relief Foundation, Hare Krishna Land, Juhu, Mumbai –400049", without any change in the approved cost of Rs. 10.55 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with the financial year 2015-16 i.e 2015-16, 2016-17 & 2017-18.

[No. 204/2015/ F. No. V.27015/2/2015-SO (NAT.COM)] MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2015

का.आ. 1992(अ).—जबिक आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 29 अक्तूबर, 2003 की अधिस्चना सं. का.आ. 1124(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "पर्यावरण में प्लास्टिक के लिए भारतीय केंद्र, दूसरा तल, कुशेश मैन्सन, 22, कावसाजी पटेल स्ट्रीट और 48/54, जन्मभूमि मार्ग, फोर्ट मुंबई-400001" द्वारा "पर्यावरण हितैषी तरीके से प्लास्टिक अपिषण्ट का पुरश्चक्रण पुनर्लाभ पुनःउपयोग" की परियोजना को निर्धारण वर्ष 2004-05 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 10 पर विनिर्दिष्ट किया था; जिसे बाद में दिनांक 4 अक्तूबर, 2006 की अधिस्चना सं. का.आ. 1424(अ) के तहत वित्तीय वर्ष 2006-2007 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 18 मई, 2009 की अधिस्चना सं. का.आ. 1262(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 12 मार्च, 2013 की अधिस्चना सं. का.आ. 663(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

जबिक दिनांक 4 अक्तूबर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1424(अ) द्वारा संस्थान का पता बदल दिया गया था

और जबिक दिनांक 14 अक्तूबर, 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 2605(अ) द्वारा लागत को 10.00 करोड़ रूO से बढ़ाकर 20.00 करोड़ रूपये कर दिया गया था;

और जबिक उक्त परियोजना या स्कीम के 12 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबिक सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अविध के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसिलए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा "पर्यावरण में प्लास्टिक के लिए भारतीय केंद्र, दूसरा तल, कुशेश मैन्सन, 22, कावसाजी पटेल स्ट्रीट और 48/54, जन्मभूमि मार्ग, फोर्ट मुंबई-400001" द्वारा चलाई जा रही "पर्यावरण हितैषी तरीके से प्लास्टिक अपशिष्ट का पुरश्चक्रण पुनर्लाभ पुन:उपयोग" की परियोजना अथवा स्कीम को 20.00 करोड़ रूपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अविध अर्थात 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. **205**/2015/फा. सं. वी-27015/2/2015-एस ओ (रा.स.)] मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2015

**S.O. 1992(E).**— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.1124(E) dated the 29th October, 2003, issued under clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 10, "Recycle Recover Reuse of plastic waste in an eco-friendly manner" by "Indian Centre for Plastics in the Environment, 2nd Floor, Kushesh Mansion, 22, Cawasji Patel Street and 48/54, Janmabhoomi Marg, Fort Mumbai – 400001", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2004-2005, which was extended further vide notification number S.O.1424(E) dated the 4th October, 2006 for a period of three years beginning with financial year 2006-2007, which was extended further vide notification number S.O.1262(E) dated the 18th May, 2009 for a period of three years beginning with financial year 2009-2010 and which was extended further vide notification number S.O.663(E) dated the 12th March, 2013 for a period of three years beginning with financial year 2012-2013;

And whereas by notification number S.O.1424(E) dated 4th October, 2006 the address of the institution was changed;

And whereas by notification number S.O. 2605 (E) dated 14th October, 2009, the cost was enhanced from Rs. 10.00 crore to Rs. 20.00 crore;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond twelve years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by subsection (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project "Recycle Recover Reuse of plastic waste in an eco-friendly manner", which is being carried out by "Indian Centre for Plastics in the Environment, 2nd Floor, Kushesh Mansion, 22, Cawasji Patel Street and 48/54, Janmabhoomi Marg, Fort Mumbai–400001", without any change in the approved cost of Rs. 20.00 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with the financial year 2015-16 i.e 2015-16, 2016-17 & 2017-18.

[No. 205/2015/ F. No. V.27015/2/2015-SO (NAT.COM)] MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2015

का.आ. 1993(अ).—जबिक आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 13 मार्च, 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 737(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "सेवालय, सेवालय परिसर, कसुवा गांव, डाकघर पक्कम, समीप तिरूनिनरावुर-602024" द्वारा "चिन्ड्रन होम प्रोजेक्ट" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2009-10 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 4 पर अधिसूचित किया था; जिसे बाद में दिनांक 27 दिसंबर, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 2898(अ.) और दिनांक 26.10.2012 के शुद्धिपत्र सं. का.आ. 2560(अ.) के तहत वित्तीय वर्ष 2012-13 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था;

और जबिक उक्त परियोजना या स्कीम के 6 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है :

और जबिक सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अविध के लिए बढाने की सिफारिश की है:

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, "सेवालय, सेवालय पिरसर, कसुवा गांव, डाकघर पक्कम, समीप तिरूनिनरावुर-602024" द्वारा चलाई जा रही "चिन्ड्रन होम प्रोजेक्ट" की पिरयोजना अथवा स्कीम को 3.00 करोड़ रूपये की कॉर्पस निधि सिहत 3.63 करोड़ रू0 की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अविध अर्थात 2015-16, 2016-17 और 2017-2018 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. **206**/2015/फा. सं. वी-27015/2/2015-एस ओ (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2015

**S.O. 1993(E).**— Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 737(E) dated 13th March, 2009, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 4, "Children's Home Project" by "Sevalaya, Sevalaya Campus, Kasuva Village, Pakkam Post, Near Thiruninravur-602024", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2009-10 and which was extended further vide notification number S.O. 2898(E) dated the 27th December, 2011 and a corrigendum S.O. No. 2560 (E) dated 26.10.2012 for a period of three years beginning with financial year 2012-2013;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Sevalaya Primary School Building Project" which is being carried out by "Sevalaya, Sevalaya Campus, Kasuva Village, Pakkam Post, Near Thiruninravur-602024", without any change in the approved cost of Rs. 3.63 crore including a corpus fund of Rs. 3.00 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with the financial year 2015-16 i.e 2015-16, 2016-17 & 2017-18.

[No. 206/2015/ F. No. V.27015/2/2015-SO (NAT.COM)] MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2015

का.आ. 1994(अ).—जबिक आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 12 मार्च, 2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 627(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "जीवन ज्योत रिलीफ एंड केयर ट्रस्ट, 3/9, कोंडाजी चाल, जर्बई वाडिया रोड, समीप टाटा अस्पताल, पारेल-12, मुंबई, महाराष्ट्र" द्वारा "जीवन ज्योत कैंसर रिलीफ एंड केयर ट्रस्ट के वर्तमान क्रियाकलापों को जारी रखने" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अविध के लिए 10 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 3 पर अधिसूचित किया था;

और जबिक उक्त परियोजना या स्कीम के 3 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबिक सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अविध के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, "जीवन ज्योत रिलीफ एंड केयर ट्रस्ट, 3/9, कोंडाजी चाल, जर्बई वाडिया रोड, समीप टाटा अस्पताल, पारेल-12, मुंबई, महाराष्ट्र" द्वारा चलाई जा रही "जीवन ज्योत कैंसर रिलीफ एंड केयर ट्रस्ट के वर्तमान क्रियाकलापों को जारी रखने" की परियोजना अथवा स्कीम को 10.00 करोड़ रू० की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अविध अर्थात् 2015-16, 2016-17 और 2017-2018 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 207/2015/फा. सं. वी-27015/2/2015-एस ओ (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th July, 2015

**S.O. 1994(E).**— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 627(E) dated 12.03.2013 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 3, "Maintaining Present Activities of Jeevan Jyot Cancer Relief & Care Trust" by "Jeevan Jyot Cancer Relief & Care Trust, 3/9, Kondaji Chawl, Jerbai Wadia Road, Near Tata Hospital, Parel – 12, Mumbai, Maharashtra", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 10 crore for a period of three years ending with financial year 2014-15;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Maintaining Present Activities of Jeevan Jyot Cancer Relief & Care Trust", which is being carried out by "Jeevan Jyot Cancer Relief & Care Trust, 3/9, Kondaji Chawl, Jerbai Wadia Road, Near Tata Hospital, Parel – 12, Mumbai, Maharashtra", without any change in the approved cost of 10.00 crore for a further period of three years commencing with financial year 2015-16 i.e 2015-16, 2016-17 & 2017-18.

[No. 207 /2015/ F. No. V.27015/2/2015-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2015

का.आ. 1995(अ).—जबिक आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 6 अगस्त, 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 2033(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "खेरवाड़ी सामाजिक कल्याण संघ, परिश्रमालय बांद्रा (ई॰), मुंबई-400051" द्वारा "कम शिक्षित वंचित युवावर्ग के लिए युवा परिवर्तन-सेकंड चांस स्कूल ऑफ विजनेस (अखिल भारत में 80 आऊटरीच केंद्र)" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2011-12 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अविध के लिए 9.75 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 3 पर अधिसूचित किया था; जिसे बाद में दिनांक 17 अक्तूबर, 2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 3145(अ) के तहत वित्तीय वर्ष 2012-13 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबिक उक्त परियोजना या स्कीम के 6 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबिक सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अविध के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, "खेरवाड़ी सामाजिक कल्याण संघ, पिरश्रमालय बांद्रा (ई॰), मुंबई-400051" द्वारा चलाई जा रही "कम शिक्षित वंचित युवावर्ग के लिए युवा परिवर्तन-सेकंड चांस स्कूल ऑफ विजनेस (अखिल भारत में 80 आऊटरीच केंद्र)" की परियोजना अथवा स्कीम को 9.75 करोड़ रू० की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अविध अर्थात् 2015-16, 2016-17 और 2017-2018 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. **208**/2015/फा. सं. वी-27015/2/2015-एस ओ (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2015

**S.O. 1995(E).**— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) S.O. 2033(E) dated 6th August, 2009 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 3 "Yuva Parivartan-Second Chance School of Business for less Educated Deprived youth – (80 outreach centers all over India)" by "Kherwadi Social Welfare Association, Parishramalaya Bandra (E), Mumbai – 400051", as an eligible project at the estimated cost of Rs.9.75 crore for a period of three years ending with financial year 2011-12 and which was extended further vide notification number S.O. 3145(E) dated 17.10.2013 for a period of three years beginning with financial year 2012-2013.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961),- (a) hereby notifies the scheme or project "Yuva Parivartan-Second Chance School of Business for less Educated Deprived youth – (80 outreach centers all over India)" which is being carried out by "Kherwadi Social Welfare Association, Parishramalaya Bandra (E), Mumbai – 400 051", without any change in the approved cost of Rs.9.75 crore, as an eligible project or scheme, for a further period of three years commencing with financial year 2015-16 i.e. 2015-16, 2016-17 and 2017-18.

[No. 208/2015/ F. No. V.27015/2/2015-SO (NAT.COM)] MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2015

का.आ. 1996(अ).—जबिक आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 20 मई, 2004 की अधिसूचना सं. का.आ. 604(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "एच.बी.एस. ट्रस्ट (ह्यूमन बेनेफिट्स सर्विस ट्रस्ट), 21-सी, प्रथम तल, रतानदा, जोधपुर-342001, राजस्थान" द्वारा "स्कूल और अस्पताल की स्थापना और इनके परिचालन" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2003-04 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 10 पर अधिसूचित किया था; जिसे बाद में दिनांक 29 मार्च, 2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 484(अ) के तहत वित्तीय वर्ष 2006-2007 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 17 नवंबर, 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 2910(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 9 अक्तूबर, 2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 2416(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; आर का.आ. 2416(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबिक उक्त परियोजना या स्कीम के 12 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबिक सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अविध के लिए बढाने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा "एच.वी.एस. ट्रस्ट (ख्र्मन बेनेफिट्स सर्विस ट्रस्ट), 21-सी, प्रथम तल, रतानदा, जोधपुर-342001, राजस्थान" द्वारा चलाई जा रही "स्कूल और अस्पताल की स्थापना और इनके परिचालन" की परियोजना अथवा स्कीम को 500.00 लाख रूपये की कॉर्पस निधि सिहत 937.74 लाख रूपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अविध अर्थात् 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 209/2015/फा. सं. वी-27015/2/2015-एस ओ (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th July, 2015

**S.O. 1996(E).**— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.604(E) dated the 20th May, 2004, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 10, "Establishment and running of the school and hospital" by "H.B.S. Trust, (Human Benefits Service Trust) 21-C, First Floor, Ratanada, Jodhpur – 342001, (Rajasthan)", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2003-2004, which was extended further vide notification number S.O.484(E) dated the 29th March, 2007 for a period of three years beginning with financial year 2006-2007, which was extended further vide notification number S.O. 2910(E) dated 17th November, 2009 for a period of three years beginning with financial year 2009-10 and which was extended further vide notification number S.O. 2416(E) dated 9th October, 2012 for a period of three years beginning with financial year 2012-13;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond twelve years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (a) hereby notifies the scheme or project "Establishment and running of the school and hospital" which is being carried out by "H.B.S. Trust (Human Benefits Service Trust), 21-C, First Floor, Ratanada, Jodhpur – 342001, (Rajasthan)", without any change in the approved cost of Rs. 937.74 lakh including a corpus fund of Rs. 500.00 lakh, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial year 2015-16 i.e. 2015-16, 2016-17 and 2017-18.

[No. 209 /2015/ F. No. V.27015/2/2015-SO (NAT.COM)] MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2015

का.आ. 1997(अ).—जबिक आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 12 मार्च, 2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 627(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "शेयर सोसायटी टू हील एंड रिस्टोर एजुकेट, सोलीटेयर कार्पोरेट पार्क बिल्डिंग सं.5, 7वां तल, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी (ईस्ट), मुंबई-400093, महाराष्ट्र" द्वारा "स्वच्छता, सिंचाई और स्वास्थ्य परियोजनाओं के मौजूदा प्रशिक्षण केंद्र का विस्तार" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अविध के लिए 16.66 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 20 पर अधिसूचित किया था;

और जबिक उक्त परियोजना या स्कीम के 3 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबिक सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय सिमिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस सिमिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अविध के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, "शेयर सोसायटी टू हील एंड रिस्टोर एजुकेट, सोलीटेयर कार्पोरेट पार्क बिल्डिंग सं.5, 7वां तल, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी (ईस्ट), मुंबई-400093, महाराष्ट्र" द्वारा चलाई जा रही "स्वच्छता, सिंचाई और स्वास्थ्य परियोजनाओं के मौजूदा प्रशिक्षण केंद्र का विस्तार" की परियोजना अथवा स्कीम को 16.66 करोड़ रू० की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अविध अर्थात् 2015-16, 2016-17 और 2017-2018 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिस्चित करती है।

[सं. 210/2015/फा. सं. वी-27015/2/2015-एस ओ (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th July, 2015

**S.O. 1997(E).**— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 627(E) dated 12.03.2013 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 20, "Expansion of existing Sanitation, Irrigation and Health Projects Training Centre" by "Share Society to Heal Aid Restore Educate, Solitair Corporate Park Building No. 5, 7th Floor, Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai-400093, Maharashtra", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 16.66 crore for a period of three years ending with financial year 2014-15;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Expansion of existing Sanitation, Irrigation and Health Projects Training Centre", which is being carried out by "Share Society to Heal Aid Restore Educate, Solitair Corporate Park Building No. 5, 7th Floor, Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai-400093, Maharashtra", without any change in the approved cost of Rs. 16.66 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2015-16 i.e 2015-16, 2016-17 & 2017-18.

[No. 210/2015/ F. No. V.27015/2/2015-SO (NAT.COM)] MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2015

का.आ. 1998(अ).—जबिक आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप धारा (1) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 10.01.2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 28(अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने 'भारत सेवाश्रम संघ, 211, राश बिहारी एवेन्यू, कोलकाता-700019, पश्चिम बंगाल' द्वारा 'जनजातीय कल्याण परियोजना-गंगपुर, जिला नवसारी, गुजरात में डिसपेंसरी हेतु भवन, स्कूल, होस्टल, लघु उद्योग, तकनीकी प्रशिक्षण/व्यावसायिक प्रशिक्षिण संस्थान, सांस्कृतिक हॉल, आश्रम कॉम्प्लेक्स, आवासीय क्वार्टर, वाटर टैंक, आदि के निर्माण' की परियोजना को निर्धारण वर्ष 2001-2002 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 2 पर अधिसूचित किया था; जिसे आगे दिनांक 05.08.2003 की अधिसूचना सं. का.आ. 897(अ) द्वारा निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; जिसे आगे दिनांक 29.03.2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 485(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था और जिसे आगे दिनांक 10.08.2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 2053(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-2010 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था और जिसे आगे दिनांक 12.03.2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 649(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-2013 को प्रारम्भ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबिक उक्त परियोजना अथवा स्कीम के पंद्रह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबिक सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे तीन वर्षों की अविध के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है।

इसिलए, अब, केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा, 'भारत सेवाश्रम संघ, 211, राश बिहारी एवेन्यू, कोलकाता-700019, पश्चिम बंगाल' द्वारा चलाई जा रही 'जनजातीय कल्याण परियोजना-गंगपुर, जिला नवसारी, गुजरात में डिसपेंसरी हेतु भवन, स्कूल, होस्टल, लघु उद्योग, तकनीकी प्रशिक्षण/व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, सांस्कृतिक हॉल, आश्रम कॉम्प्लेक्स, आवासीय क्वार्टर, वाटर टैंक, आदि के निर्माण' की परियोजना को, 277.00 लाख रुपये की अनुमादित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना, वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अविध अर्थात 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. **21**1/2015/फा. सं. वी-27015/2/2015-एस ओ (रा.स.)] मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्टीय समिति)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th July, 2015

**S.O. 1998(E).**— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O.28(E) dated the 10th January, 2001, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 2, "Tribal Welfare Project – construction of building for dispensary, schools, hostel, small scale industries, technical training/vocational training institute, cultural hall, Ashram complex, residential quarters, water tank etc. at Gangpur, District Navsari, Gujarat" by Bharat Sevashram Sangha, 211, Rash Behari Avenue, Kolkata –700019, West Bengal, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2001-2002, which was extended further vide notification number S.O.897(E) dated the 5th August, 2003 for a period of three years beginning with assessment year 2004-2005, which was extended further vide notification number S.O.485(E) dated the 29th March, 2007 for a period of three years beginning with financial year 2006-2007 and which was extended further vide notification number S.O. 2053(E) dated 10th August, 2009 for a period of three years beginning with financial year 2009-10 and which was extended further vide notification number S.O. 649(E) dated 12th March, 2013 for a period of three years beginning with financial year 2012-13;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond fifteen years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Tribal Welfare Project – construction of building for dispensary, schools, hostel, small scale industries, technical training/vocational training institute, cultural hall, Ashram complex, residential quarters, water tank etc. at Gangpur, District Navsari, Gujarat", which is being carried out by Bharat Sevashram Sangha, 211, Rash Behari Avenue, Kolkata –700019, West Bengal, without any change in the approved cost of Rs. 277.00 lakhs, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial year 2015-16 i.e 2015-16, 2016-17 & 2017-18.

[No. 211/2015/ F. No. V.27015/2/2015-SO (NAT.COM)] MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2015

का.आ. 1999(अ).—जबिक आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 12.03.2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 627(अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने "कलकत्ता रेसक्यू, पंजीकृत कार्यालय-10, नीलमोनी मित्रा स्ट्रीट, कोलकाता-700 006, पश्चिम बंगाल" द्वारा "कलकत्ता रेसक्यू " की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए 18.57 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 5 पर अधिसूचित किया था;

और जबिक उक्त परियोजना अथवा स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है:

और जबिक सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अविध के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है।

इसलिए, अब, केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा, "कलकत्ता रेसक्यू, पंजीकृत कार्यालय-10, नीलमोनी मित्रा स्ट्रीट, कोलकाता-700 006, पश्चिम बंगाल" द्वारा चलाई जा रही "कलकत्ता रेसक्यू " की परियोजना को 18.57 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना, वित्तीय वर्ष

2015-16 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 212/2015/फा. सं. वी-27015/2/2015-एस ओ (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th July, 2015

**S.O. 1999(E).**— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 627(E) dated 12.03.2013 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 5, "Calcutta Rescue" by "Calcutta Rescue, Regd. Office – 10, Nilmoni Mitra Street, Kolkata – 700 006, West Bengal", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 18.57 crore for a period of three years ending with financial year 2014-15;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Calcutta Rescue", which is being carried out by "Calcutta Rescue, Regd. Office – 10, Nilmoni Mitra Street, Kolkata – 700 006, West Bengal", without any change in the approved cost of Rs. 18.57 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2015-16 i.e 2015-16, 2016-17 & 2017-18.

[No. 212 /2015/ F. No. V.27015/2/2015-SO (NAT.COM)] MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2015

का.आ. 2000(अ).—जबिक आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप धारा (1) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 05.07.2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 998(अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने "बालग्राम एस.ओ.एस. चिलड्रेन्स विलेज्स, अर्जुन बिल्डिंग, कोरेगॉव रोड, पुणे - 411001" द्वारा "बालग्राम एस.ओ.एस. चिलड्रेन्स विलेज्स" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 1 पर अधिसूचित किया था; जिसे आगे दिनांक 25.03.2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 854(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-2010 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था और जिसे आगे दिनांक 12.03.2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 642(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-2013 को प्रारम्भ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबिक उक्त परियोजना अथवा स्कीम के नौ वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबिक सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अविध के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है।

इसलिए, अब, केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा, "बालग्राम एस.ओ.एस. चिलड्रेन्स विलेज्स, अर्जुन बिल्डिंग, कोरेगाँव रोड, पुणे - 411001" द्वारा चलाई जा रही "बालग्राम एस.ओ.एस. चिलड्रेन्स विलेज्स" 'की परियोजना को 2.00 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना, वित्तीय

वर्ष 2015-16 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 213/2015/फा. सं. वी-27015/2/2015-एस ओ (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th July, 2015

**S.O. 2000(E).**— Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.998(E) dated the 5th July, 2006, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 1, "Balgram SOS Children's Villages" by "Balgram SOS Children's Villages, Arjun Building, Koregaon Road, Pune – 411001", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2006-2007, which was extended further vide notification number S.O. 854(E) dated 25th March, 2009 for a period of three year beginning with financial year 2009-10 and which was extended further vide notification number S.O. 642(E) dated 12th March, 2013 for a period of three year beginning with financial year 2012-13;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond nine years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Balgram SOS Children's Villages" which is being carried out by "Balgram SOS Children's Villages, Arjun Building, Koregaon Road, Pune – 411001", without any change in the approved cost of Rs. 2.00 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial year 2015-16 i.e 2015-16, 2016-17 & 2017-18.

[No. 213/2015/ F. No. V.-27015/2/2015-SO (NAT.COM)] MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2015

का.आ. 2001(अ).—जबिक आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 12.03.2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 627(अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने "पालना रेड्डी मेमोरियल चेरीटेबल ट्रस्ट, फ्लेट सं. 803, आई-ब्लाक, जल वायु टावर्स, लोअर टैंक बंद, हैदराबाद - 50048, ऑध्र प्रदेश" द्वारा "वर्तमान वृद्धाश्रम और अनु. जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति और गरीबी रेखा के नीचे वृद्ध व्यक्तियों के लिए शीघ्र बनने वाले 200 वृद्धों हेतु वृद्धाश्रम की गतिविधियाँ बढ़ाने" की परियोजना को 446.83 लाख रुपये की अनुमानित लागत से वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अविध के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 26 पर अधिसूचित किया था

और जबिक उक्त परियोजना अथवा स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है:

और जबिक सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय सिमिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस सिमिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अविध के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है।

इसलिए, अब, केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा, "पालना रेड्डी मेमोरियल चेरीटेबल ट्रस्ट, फ्लेट सं. 803, आई-ब्लाक, जल वायु टावर्स, लोअर टैंक बंद, हैदराबाद - 50048, ऑध प्रदेश" द्वारा चलाई जा रही "वर्तमान वृद्धाश्रम और अनु. जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति और गरीबी रेखा के नीचे वृद्ध ट्यिक्तियों के लिए शीघ्र बनने वाले 200 वृद्धों हेतु वृद्धाश्रम की गतिविधियाँ बढ़ाने" की परियोजना को, 446.83 लाख रुपये की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना, वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अविध अर्थात 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 214/2015/फा. सं. वी-27015/2/2015-एस ओ (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th July, 2015

**S.O. 2001(E).**— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 627(E) dated 12.03.2013 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 26, "Enhancement of the activities of present old age home and upcoming 200 old aged SC/ST/OBC & Below Poverty Line Persons" by "Palana Reddy Memorial Charitable Trust, Flat No. 803, I-Block, Jal Vayu Towers, Lower Tank Bund, Hyderabad – 50048, Andhra Pradesh", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs.446.83 lakh for a period of three years ending with financial year 2014-15;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Enhancement of the activities of present old age home and upcoming 200 old aged SC/ST/OBC & Below Poverty Line Persons", which is being carried out by "Palana Reddy Memorial Charitable Trust, Flat No. 803, I-Block, Jal Vayu Towers, Lower Tank Bund, Hyderabad –50048, Andhra Pradesh", without any change in the approved cost of Rs. 446.83 lakh, for a further period of three years commencing with financial year 2015-16 i.e. 2015-16, 2016-17 & 2017-18.

[No. 214/2015/ F. No. V.27015/2/2015-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)